● वर्ष-3
● अंक-31
रायपुर, गुरुवार
14 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों

मोदी की अंतरराष्ट्रीय नीति में 3 सूत्रीय कॉकटेल

जी20 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत का डंका दुनियाभर की चौपालों पर बज रहा है। जी0 समिट में सभी देशों की सहमति से घोषणापत्र भी जारी किया गया। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक और राजनयिक जीत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आम सहमति की संभावना जब न के बराबर लग रही थी तब भारत की कोशिशें रंग अफ्रीका का आना लाई। यह भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। यह दिखाता है कि विश्व को साथ लाने में भारत की भूमिका काफी अहम है। विदेश सेवा के भारतीय राजनयिकों, सदस्य देशों के साथ कई महीनों की कड़ी मेहनत और 3 सितंबर से रात भर जागने वाले पांच लोगों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था कि सहमति बनाने में कामयाबी हासिल हो पाई। टीम मोदी ने चाणक्य नीति को चरितार्थ कर दिया। युद्ध और शांति काल में विदेश नीति का पुराना और आजमाया हुआ ग्रंथ चाणक्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य की साम, दाम, दंड, भेद वाली नीति से तो आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांत भी बड़े काम के हैं। इसमें जो रणनीतियाँ शामिल हैं उनमें शामिल हां, संधि (ट्रीटी), विग्रह (संधि तोड़ना और युद्ध शुरू करना), आसन (तटस्थता), यना (युद्ध के लिए मार्च की तैयारी), सामश्रय (समान लक्ष्य रखने वालों के साथ हाथ मिलाना) और अंत में द्वैदभाव (दोहरी नीति यानी एक दुश्मन से कुछ समय के लिए दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी)। संधि (शांति स्थापित करना) की नीति इस नियम पर आधारित है कि जब किसी राज्य को अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है, तो उसे जीवित रहने के लिए शांतिपूर्ण समझौते पर बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि शांति स्थापित करने के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाए तो इसे कई ऐतिहासिक शांति संधियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। कौटिल्य संधि के अन्य रूपों, काल संधि (अस्थायी गठबंधन) या स्थावर संधि (स्थायी गठबंधन) की भी बात करते हैं, जिसमें एक छोटा राज्य अधिक शक्तिशाली सहयोगी को सेवा प्रदान करके और शक्तिशाली लोगों के साथ गठबंधन में रहकर रहने का सौदा कर सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि अगर राजा को लगे कि दुश्मन की सेना की ताकत समान है और जंग लड़ने का मतलब है दोनों तरफ तबाही का खुला निमंत्रण को ऐसी परिस्थिति में समझौता यानी तटस्थ रहकर शांति का प्रयास आवश्यक है। जवाहर लाल नेहरू ने कौटिल्य की आसन नीति अपनाई जिसका परिणाम ती गुटनिरपेक्षता और मोदी ने कौटिल्य की संधि, आसन और सामरस्य नीति का कॉकटेल तैयार किया। नई दिल्ली ने अपने घोषणापत्र के जरिए चीन को भी अपरोक्ष रूप से साधा। लेकिन इसमें कहीं भी लद्दाख या एलएसी का जिक्र नहीं था और न ही अरुणाचल प्रदेश में उसकी हरकतों का उल्लेख था। लेकिन इस घोषणापत्र में परोक्ष रूप से वो सब था जो भारत चाहता था।

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक

एजेंडे पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक इस सत्र को लेकर एजेंडा साफ नहीं किया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जता रहा है। इस बीच सरकार ने विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस ने विशेष सत्र का एजेंडा साफ न बताने के लिए मोदी सरकार को घेरा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिना नाम लिए कहा कि सिर्फ दो ही लोगों को विशेष सत्र का एजेंडा पता है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, आज 13 सितंबर है और विशेष सत्र को शुरू होने में सिर्फ पांच दिन हैं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति (हो सकता है दूसरे व्यक्ति) को ही इसके एजेंडे के बारे में जानकारी है।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, सांसदों ने दिए सुझाव

केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों संसद सत्र के दौरान आपराधिक न्याय विधेयक पेश किए गए थे। इनमें आईपीसी की जगह लेने वाला भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, सीआरपीसी की जगह लेने वाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाला भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। इन विधेयकों की जांच एक संसदीय समिति द्वारा की जा रही है। अब विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि पूर्व सीजेआई यूयू ललित और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर को भी इस जांच समिति में शामिल किया जाए।

अदाणी मामले में जेपीसी की मांग

कांग्रेस ने अदाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग बुधवार को फिर उठाई और कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी के गठन की घोषणा के साथ संसद के नए भवन में कामकाज का आगाज होना चाहिए।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया है कि अडाणी समूह से संबंधित एक पूर्व कांट्रैक्टर ने उच्चतम न्यायालय से इस समूह से संबंधित मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। अमेरिकी कंपनी 'हिंडनबर्ग रिसर्च' द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ 'अनियमितताओं' और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमले और जेपीसी से जांच की मांग कर रही है। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और उसका कहना था कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है।

विपक्षी सांसदों ने दिए ये सुझाव

संसदीय समिति में शामिल विपक्ष के एक सांसद ने 16 विशेषज्ञों की एक लिस्ट जमा की है, जिसमें वरिष्ठ वकील फाली एस नरीमन और वकील मेनका गुरुस्वामी का नाम भी शामिल है। ये भी सुझाव दिया गया है कि समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के साथ ही बार काउंसिल के सदस्यों, कानून के जानकारों, जेल अधिकारियों और सुधार कार्यकर्ताओं के साथ ही धार्मिक नेताओं और साइबर क्राइम विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

विपक्षी सांसदों ने लगाए थे आरोप

विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति में शामिल एक और विपक्षी सांसद ने कहा है कि जिस तेजी से विधेयकों की जांच की जा रही है, उसे देखते हुए इस काम में एक या डेढ़ साल का लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस काम में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इन विधेयकों का बड़ा असर होगा। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपनी बात रखने के पर्याप्त मौके नहीं दिए जा रहे हैं। संसदीय समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। जिसके बाद इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। इन विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद ब्रजलाल कर रहे हैं।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम
सरकार कर रही परामर्श

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यस्थता और सुलह कानून, 1996 में प्रस्तावित संशोधन के लिए परामर्श प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थतों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई टाल दी है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए और कोर्ट को बताया कि देश में मध्यस्थता कानून के मुद्दे पर गठित की गई विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब समिति की रिपोर्ट नवंबर की शुरुआत तक मिल सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई टाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट नवंबर में इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी सवाल पर सुनवाई कर रहा है कि क्या मध्यस्थता के लिए अयोग्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है या नहीं। इस मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मितल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

पीएम मोदी का आज रायगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार (14 सितंबर) को रायगढ़ आएंगे। बृहस्पतिवार को दोपहर 2.15 बजे भारतीय वायु सेना के विमान से जिंदल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से कोड़ातराई पहुंचेंगे। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री लगभग 6,350 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 'क्रिटिकल केयर ब्लॉक' की आधारशिला भी रखेंगे। इतना ही नहीं, एक लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे। इसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कोड़ातराई आमसभा में 15 विधानसभा के लोग शामिल होंगे। इसके लिए छह डोम बनाए जाएंगे। इसमें तीन ग्रीन रूम भी बनेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ दौरे के दौरान कोयला, रेल, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री भी उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम के समापन के बाद पीएम मोदी कोड़ातराई में आम सभा को तीन से चार बजे तक संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कोड़ातराई एयरपोर्ट के एक किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही दोपहर दो बजे के बाद दो घंटा के लिए रायगढ़-सारंगढ़ एनएच पर भारी वाहन का परिचालन प्रतिबंध किया गया है। पूरे कार्यक्रम के समापन के बाद पीएम वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को करीब एक लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। जिसे लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही जिला भाजपा घर-घर जाकर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रही हैं। इसी तैयारी का जायजा लेने बीते 10 सितंबर को केंद्रीय मंत्री केन्द्रीय मंत्री और चुनाव सहप्रभारी मनसुख मंडाविया और प्रदेश सहप्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे थे। परिवर्तन यात्रा और प्रधानमंत्री की आमसभा की तैयारी की समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए रायपुर पहुंचे थे। इसके बाद गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 28 सितंबर को फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर आ सकते हैं। परिवर्तन यात्रा के समापन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। पहली यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव खुद करेंगे। दूसरी यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। दोनों यात्राएं 87 विधानसभा क्षेत्रों की 2 हजार 989 किमी की यात्रा तय करेंगी। अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट भूपेश सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। बीजेपी ने जो यात्रा का रोडमैप बनाया है, उसके तहत यात्रा प्रतिदिन तीन विधानसभा के दौरे पर रहेगी। इसमें हर दिन एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक 'तीजा- पोरा पर्व' के अवसर पर हर वर्षो की तरह इस वर्ष भी 14 सितम्बर को दोपहर 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए यहां जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। तीन दिनों तक चलने वाले पारंपरिक तीजा- पोरा पर्व का उत्साह पूरे छत्तीसगढ़ में अब जोरों पर दिखाई पड़ रहा है। बाजारों में रौनक है और तिजहरिन माता-बहनें, किसान भाई और आम जन इस त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ मनाने हेतु तैयारियों में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्वों को अपने निवास में मनाने की शुरूआत की है। इसी कड़ी में तीजा-पोरा पर्व की तैयारियां मुख्यमंत्री निवास में की जा रही है।

प्रमुख समाचार

मध्य प्रदेश से चुनावी बिगुल फूकेंगा इनेडेइए गठबंधन

नईदिल्ली। विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी चुनावी अभियान की शुरूआत करने जा रहा है। इसकी शुरूआत चुनावी राज्य मध्य प्रदेश से होगी। साझा बयान में कहा गया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी पहली राजनीतिक रैली आयोजित करेगा। यह बुधवार को इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति की पहली बैठक के बाद आया। विपक्ष के 14 सदस्यीय पैनल की बैठक दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर हुई। गठबंधन ने एक संयुक्त बयान में कहा गया कि समन्वय समिति ने सीट बंटवारे के निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि सदस्य दल बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के बाद कहा कि 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दल सीट बंटवारे पर बातचीत करेंगे और इस पर जल्द से जल्द फैसला करेंगे। राकांपा के प्रमुख शरद पवार के नई दिल्ली स्थित आवास पर यह बैठक हुई। बैठक के बाद सपा नेता जावेद अली खान ने कहा, ...सीट बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।

कांग्रेस में पार्टी का विलय कर सकती हैं वाईएस शर्मिला

नईदिल्ली। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। वह अपने राजनीतिक दल वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले पर सोमवार को जानकारी निकल कर सामने आई थी। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला हैं। बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस की मेगा रैली होनी है। इसमें भी वाईएस शर्मिला के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले हाल ही में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात की थी। जब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से शर्मिला के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण थी। लेकिन बाकी आगे की चीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा।

लखनऊ में अलकायदा आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

नईदिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उत्तर प्रदेश में अल-कायदा के एक सक्रिय सदस्य के एक घर को कुर्क किया है, जिसका इस्तेमाल आरोपी आतंकी हमलों को अंजाम देने की तैयारी के लिए कर रहा था। संदिग्ध मिन्हाज अहमद, मकान नं. की संपत्ति का उपयोग कर रहा था। 602/400, अदनानपल्ली, रिंग रोड, दुबग्गा, यूपी पर राज्य में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) और पेट्रोल बमों के निर्माण सहित विभिन्न आतंक संबंधी गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। मिन्हाज और एक अन्य संदिग्ध मसीरुदीन को 11 जुलाई, 2021 को उसी घर से गिरफ्तार किया गया था। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्ति मिन्हाज के पिता सिराज अहमद और उनकी मां और भाई के नाम पर पंजीकृत है। एनआईए ने एक बयान में कहा कि मिन्हाज द रेसिस्टेंस फ्रंट (प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध) से जुड़े

उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन

नईदिल्ली। केंद्र ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन का समर्थन करने के लिए अनुदान जारी करने की योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, तीन वर्षों में कुल 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिसका कुल वित्तीय निहितार्थ 1,650 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने चार वर्षों में लागू किए जाने वाले 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना चरण-ढ्ढढ्ढ को भी मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका लक्ष्य है ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतें स्थापित करना। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। पेपरलेस अदालतों के लिए ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज डेटा बनाया जाएगा। सभी न्यायालय परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

अनंतनाग में मुठभेड़, कर्नल समेत तीन अफसर शहीद

नईदिल्ली। बुधवार को अनंतनाग में गोलीबारी में सेना के दो वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने कहा कि गोलीबारी में भारतीय सेना के एक कर्नल और एक मेजर और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहीदों में से एक की पहचान भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल मनप्रीत सिंह के रूप में हुई। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने गडोले इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी की भी जान चली गई। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में आतंकवादियों की तलाश के लिए निकले सेना के अधिकारी सामने से जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। अधिकारी के मुताबिक कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल और एक मेजर शहीद हो गए। अधिकारी 19 आरआर की कमान संभाल रहे थे।

-

सनातन के मुद्दे पर कमजोर पड़ता विपक्ष

अभय कुमार दुबे

सनातन धर्म से संबंधित राजनीतिक विवाद में इस समय भाजपा मजे ले रही है और विपक्ष चक्कर में फंसा हुआ है। इस मौके का ज्यादा से ज्यादा दोहन भाजपा के पक्ष में जा सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि उन्हें सनातन धर्म के प्रश्न पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, और विपक्षी गठबंधन सनातन के चक्कर में क्यों फंसा- इस सवाल का उत्तर खोजने की जरूरत है। सनातन नाम की विस्फोटक सुरंग विपक्षी राजनीति की जमीन में तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति के कारण प्लांट हुई। सनातन धर्म और ब्राह्मणों के विरोध की राजनीतिक परंपरा तमिलनाडु में बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत रामस्वामी नायकर पेरियार ने डाली थी। वे स्वयं को पश्चिमी शैली में नास्तिक, बुद्धिवादी, धर्मविरोधी बता कर प्रगतिशील और रैडिकल विचारों की दावेदारी करते थे। चूंकि तमिलनाडु में मुट्ठी भर ब्राह्मण सभी फायदे की जगहों पर बैठे हुए थे और सत्ता पर भी उन्हीं का कब्जा रहता था, इसलिए जल्दी ही पेरियार की इस लाइन के इर्दगिर्द गैर-ब्राह्मण शक्तिशाली जातियों का जमावड़ा बनता चला गया। इस राजनीतिक लाइन की खास बात यह थी कि इसमें दावा कमजोर जातियों के हित का किया जाता था, पर इस राजनीति पर पकड़ मजबूत जातियों की ही थी। पहले जस्टिस पार्टी और फिर द्रविड़ कषगम के जरिये इस मुहिम ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। चूंकि हम

उत्तर भारतीय तमिल नहीं जानते, इसलिए हम पेरियार और उनके अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बेहद आक्रामक भाषा से परिचित नहीं हैं। सवाल यह है कि स्टालिन के पुत्र को पेरियार की भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की द्रविड़ राजनीति तो काफी बदल चुकी है। आज तो द्रविड़ पार्टियां बूढ़ों को तीर्थाटन कराने का वायदा करती हैं। पूरे तमिलनाडु में पौराणिक हिंदू धर्म की पूजा-अर्चना और कर्मकांडीय स्वरूप की उत्तर भारत से भी ज्यादा धूम है। द्रविड़ राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा अन्ना द्रमुक की नेता जयललिता भी मंदिर वगैरह जाती थीं। वे अपनी ब्राह्मण जातिगत पहचान को भी नहीं छिपाती थीं। उन्होंने उत्तर भारत की बनिया-ब्राह्मण पार्टी भाजपा से भी जब-तब गठजोड़ करने से भी परहेज नहीं किया। दरअसल, होता यह है कि द्रमुक के नेताओं को जैसे ही किसी राजनीतिक संकट का आभास होता है, वे तुरंत पेरियार की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, और उत्तर भारत के साम्राज्यवाद का प्रश्न भी उठा दिया जाता है। सनातन धर्म को इस साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि बताया जाता है। इस समय भाजपा तमिलनाडु में जम कर राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। उसने एक तमिल अफसर के। अन्नामलाई को अध्यक्ष बनाया है, और उनके जरिये प्रदेश में एक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें उत्तर भारत और भाजपा के खिलाफ किए जाने वाले प्रचार का खंडन किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टालिन सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना कर रही है। इस स्थिति में जरूरी है कि द्रविड़ नेता पुरानी राजनीतिक फिकरेबाजी का इस्तेमाल करें। लेकिन उत्तर भारत के जगदानंद सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है सामाजिक न्याय की राजनीति में होने वाली फिकरेबाजी का पुराना अभ्यास। यह लफ्फाजी उस समय चल जाती थी, जब मुकाबले में कांग्रेस होती थी और भाजपा का प्रभावी ओबीसीकरण नहीं हुआ था। आज वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। भाजपा ने ऊंची जातियों, पिछड़ों और दलितों के एक अच्छे खासे हिस्से का गठजोड़ बना लिया है जो उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में उसे सत्ता का सफल दावेदार बनाता है। इसलिए ब्राह्मणवाद विरोध की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले शक्तिशाली ओबीसी जातियों के नेताओं की साख पहले जैसी नहीं रह गई है। दरअसल, ये लोग पुराने जमाने की राजनीति में जी रहे हैं। राजनीति की टाइम मशीन में ये लोग पीछे अटक कर रह गए हैं। भाजपा जानती है कि आज सनातन धर्म का वैसा विरोध करने का जमाना नहीं है जैसा कभी स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में हुआ करता था। पश्चिमी उ.प्र., मध्य उ.प्र., हरियाणा और पंजाब के बहुत से हिंदू उनसे प्रभावित होकर आर्यसमाजी हो गए थे

छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने थामे ट्रेनों के पहिए

■ पटरियों पर लेटकर किया प्रदर्शन, राज्य में बदहाल ट्रेन सेवा का लगाया आरोप, मोदी सरकार को घेरा

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने बड़े स्तर पर रेल रोको आंदोलन किया। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, करगीरोड और सरगुजा के कई स्टेशनों पर कांग्रेसियों ने रेल रोकी।इस दौरान रेलवे पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी की भी खबरें सामने आई।लेकिन कांग्रेसियों ने अपना आंदोलन बंद नहीं किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली हजारों ट्रेनों को बिना किसी शेड्यूल और जानकारी के रद्द कर रही है।जिससे आम जनता परेशान हो रही है। पिछले एक साल से लगातार ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं या फिर त्यौहार आने से पहले ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं।

कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर रेलवे को लोगों के इस्तेमाल करने लायक नहीं रहने देना चाहती।केंद्र चाहती है कि रेल से आम जनता का मोह भंग हो जाए ताकि घाटा दिखाकर रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए।कांग्रेस ने ट्रेनों को रद्द करने के पीछे सोची समझी साजिश का हवाला दिया है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार रेलवे को अडानी को देना चाह रही है।

रायपुर में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत एक जनसभा से हुई।जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर के सामने एक बड़ा मंच लगाया।इस मंच से केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने हमला बोला।इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रेल रोकने के लिए रायपुर स्टेशन के अंदर प्रवेश कर गए।रेलवे पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर स्टेशन के गेट में बैरिकेड्स लगा रखे थे।जिसे कांग्रेसियों ने तोड़ दिया और स्टेशन के अंदर घुस गए।इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय पटरी पर लेट गए।

वहीं दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन में घुसकर हंगामा किया।कांग्रेस इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे की रेलवे पुलिस सिवाय देखने के कुछ ना कर सकी।कांग्रेस कार्यकर्ता स्टेशन के अंदर घुसे और पटरियों पर बैठक गए।इस दौरान अप और डाउन लाइन से आने वाली मालगाड़ियों को स्टेशन पर ही रोक दिया गया।जिसके बाद नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी रेलवे इंजन पर चढ़ गए। इस दौरान प्लेटफॉर्म में जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौजूद थे।

बिलासपुर में कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कोटा स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई। ट्रेन रुकने के बाद सैंकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता रेल की पटरी के आगे लेट गए। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबानी और अडानी हाय हाय के नारे भी लगाए।

रायगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकने का काम किया। कांग्रेस वर्कर्स ट्रेन की पटरियों पर आ गए। उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा था। जिसे लेकर वे लोग आगे बढ़ रहे थे। सभी ने पटरियों को ब्लॉक कर दिया और ट्रेनों को रोक दिया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने बताया कि यह तो महज सांकेतिक प्रदर्शन था।आने वाले दिनों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आंदोलन को और गति दी जायेगी। ताकि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को होने वाली मुसीबतों का सामना न झेलना पड़े। वहीं इस मामले में दुर्ग स्टेशन मास्टर जी प्रधान ने बताया कि इस प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाई ।

स्टेशन मास्टर दुर्ग ने कहा ट्रेनों को आउटर पर रोककर रखा गया। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन डीआरएम के पास भेजा जाएगा।साथ ही रेलवे कार्य में बाधा पहुंचाने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने रेल रोकने के लिए स्टेशन की ओर कूच किया।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए राजनांदगांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

भाजपा की बैठक में व्यापारियों ने किया व्यापारी विकास बोर्ड बनाने की मांग

तिल्दा। तिल्दा नेवरा के विश्रामगृह सासाहोली में पिछले मंगलवार को भाजपा पदाधिकारियों और व्यापारियों के बीच बैठक आयोजित की गई जिसमें व्यापारियों से सुझाव मांगे गए। इस दौरान व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ में व्यापारियों के विकास एवं उनकी समस्याओं के लिए व्यापारी विकास बोर्ड बनाने की मांग की और इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करने कहा। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के प्रवासी विधायक बुद्धराय टुडू, भाजपा के वरिष्ठ पंडित मालूराम शर्मा के अलावा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने सुझाव रखे।

बैठक में विधायक बुद्धराय टुडू ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आवश्यक विचार-विमर्श किया। इस दौरान कार्यकर्ता ने अपना सुझाव दिया और कुछ भाजपा संगठन से जुड़े व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ में व्यापारियों के विकास एवं उनकी समस्याओं के लिए व्यापारी विकास बोर्ड बनाने की मांग की और इसे आगामी चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने का सुझाव दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता को ही टिकट मिले जो सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले।

विगत 3 विधानसभा चुनाव में भाजपा के अधिकृत उम्मीद्वार बलौदाबाजार से ही दिया जा रहा है, जबकि सर्वाधिक मतदाता तिल्दा- नेवरा क्षेत्र से ही है। उक्त बैठक में सालो से पार्टी में सक्रिय रहे, कार्यकर्ता को ही टिकट देने की मांग की गई। उक्त बैठक में प्रदेश, जिला, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षदों सहित बूथ संयोजक उपस्थित थे।

सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने गर्भवती महिला की कराई डिलीवरी

■ सड़क पर सुरक्षित प्रसव कराया, बचाई महिला और बच्ची की जान

सुकमा। बस्तर के सुकमा जिले में नक्सली मोर्चे पर तैनात जवानों ने मानवता का परिचय दिया है। यहां एक महिला को डिलीवरी के लिए उसके परिजन कांवड़ पर लेकर जा रहे थे। तभी उसको प्रसव पीड़ा हुई। महिला प्रसव पीड़ा से कराह उठी। जिसके बाद वहां पर सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराने का काम किया है। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अभी जज्जा बच्चा दोनों ठीक है। सीआरपीएफ के इस काम की हर ओर तारीफ हो रही है। परिजनों ने बच्ची का नाम भारती रखा है। यह पूरी घटना मंगलवार की है।

गांव वालों ने बताया कि महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई। तो उसके परिजन उसे कांवड़ से नजदीकी अस्पताल लेकर जा रहे थे। इस बात की जानकारी सीआरपीएफ के जवानों को मिली। जिसके बाद सीआरपीएफ जवानों ने महिला को सीआरपीएफ के अस्पताल में दाखिल कराने का फैसला लिया। लेकिन महिला को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जिसके बाद महिला की डिलीवरी के बारे में सीआरपीएफ के जवानों ने फैसला लिया। महिला की बिगड़ती स्थिति को लेकर जवानों ने सड़क पर ही महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई। जिसके बाद उन्हें उपचार और देखभाल के लिए एम्बुलेंस बुलाकर नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया।

बच्ची के सुरक्षित प्रसव के बाद सीआरपीएफ के कमांडेंट ने एलान किया कि बच्ची को सीआरपीएफ की तरफ से गोद लिया जाएगा। बच्ची के पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ उठाएगी। महिला और बच्ची की जान बचाए जाने के बाद पेद्दागुलेर गांव के लोग सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने बच्ची के नामांकरण की गुजारिश की। जिसके बाद बच्ची का नाम भारती रखा गया। जिसे गांव वालों और बच्ची के परिजन ने मान लिया।

नक्सल प्रभावित बस्तर का सुकमा जिला बेहद पिछड़ा हुआ है। यहां आजादी के सात दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं हो पाई है। अंदरुनी इलाकों में न तो बेहतर सड़क है। न ही पुल पुलिया है। जिससे स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपात स्थिति में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर नक्सल समस्या की वजह से भी विकास कार्य में काफी दिक्कतों का सामना सरकार और जिला प्रशासन को करना पड़ रहा है।

मेडिकल कॉलेज से फरार हुए हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा की पुलिस ने हत्या के उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जो मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। घटना के एक घंटे के भीतर ही पुलिस ने रजगामार मार्ग पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस ने भी राहत की सांस ली है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में दाखिल हत्या का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि, दो घंटे के बाद ही पुलिस ने उसे रजगामार मार्ग में घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। बालको थाना क्षेत्र के ग्राम गहनिया खेतार में अमर सिंह मांझी ने अपने तीन वर्षीय पुत्र की गला रेतकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसने खुद भी अपना गला काटकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था जिसमें विफल होने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस दौरान आरोपी पुलिस कर्मियों की आंखो में धूल झोंककर मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था।

उच्च अधिकारियों की इसकी सूचना दी गई। जहां घेराबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान घटना के 2 घंटे बाद आरोपी रजगामार रोड पर बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा और जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया।

संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का शुभारंभ बस्तर संभाग के 2400 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की पारम्परिक खेल विधाओं की विरासत को पुनर्जीवित कर इन खेल विधाओं से नई पीढ़ी को जोड़ने का सार्थक प्रयास छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक है। इसकी शुरुआत कर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहल के साथ ही इन खेल विधाओं के जरिये गांव से शहर के प्रतिभाओं को उभरने का बेहतर अवसर सुलभ कराया है। जिससे छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ प्रतिभा दिखा रहे हैं।

इस संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में बस्तर संभाग के सभी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य स्तर में अपना परचम लहरायें और बस्तर का नाम रोशन करें। यह बात संसदीय सचिव रेखचन्द जैन ने स्थानीय लालबाग खेल मैदान में संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के शुभारंभ करने के पश्चात खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा।

इस अवसर पर कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े ने स्वागत उदबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांव से लेकर राज्य स्तर तक पारम्परिक खेलों के प्रतिभाओं को अपने दक्षता को प्रदर्शन करने मौका मिला है।

इस संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक में 16 विभिन्न खेल विधाओं में तीन आयु वर्ग के 2400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

13 से 14 सितम्बर तक आयोजित दो दिवसीय संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक 2023 में कब्बडी, खो-खो, रस्साकशी, सँखली, पिट्ठुल, कंचा-बाटी, गिल्ली-डंडा, लंगड़ी दौड़, 100 मीटर दौड़, लम्बी कूद, गेड़ी दौड़, रस्सीकूद, फुगड़ी, भौंरा, बिल्लस एवं कुश्ती खेल विधाओं में 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन बिलासपुर में मालगाड़ियां रोकी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द करने लेकर बुधवार को कांग्रेस का प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ। बिलासपुर जिले के करगी रोड कोटा स्टेशन में सुबह पांच बजे से सात बजे तक मालगाड़ियों को रोककर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह पांच बजे से पहले ही कोटा रेलवे स्टेशन पर जा धमके और उन्होंने रेल प्रबंधन द्वारा लगातार गाड़ियां रद्द करने के खिलाफ जोरदार नारे लगाते हुए स्टेशन के अप एंड डाउन दोनों रेल लाइनों की घेराबंदी कर दी और नारेबाजी की। कार्यकर्ता पटरियों पर लेट गए और गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी।

भिलाई में वाहन चेकिंग में मिले साढ़े 9 लाख कैश

भिलाई। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल होने के कारण लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। इस बीच भिलाई में चेकिंग के दौरान पुलिस को साढ़े 9 लाख रुपये कैश मिले। वाहन में बैठे व्यापारी ने कैश से संबंधित कोई सही जानकारी नही दी। पुलिस ने आयकर विभाग को इसे लेकर पत्र भेजा है। दरअसल, ये पूरा मामला भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र का है। यहां चुनाव को देखते हुए लगातार वाहन की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान 12 और 13 सितंबर की दरम्यानी रात को पुलिस ने एक वाहन से साढ़े 9 लाख रुपये कैश बरामद किए। वाहन में एक व्यापारी बैठा था। व्यापारी से जब पुलिस ने कैश संबंधित दस्तावेज मांगे तो व्यापारी की ओर से पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने व्यापारी को एक सप्ताह के अंदर कैश के संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा है। साथ ही पुलिस ने कैश को जब्त कर आयकर विभाग को इस बारे में एक पत्र लिखा है।

शव दफनाने को लेकर बस्तर में विवाद, पुलिसबल तैनात

जगदलपुर। शव दफनाने को लेकर बस्तर में एक बार फिर विवाद की स्थिति बनी है। दरभा थाना क्षेत्र के धुमागुड़ा में मंगलवार रात बुधरी कश्यप की मौत हो गई। वह शुगर की बीमारी से पीड़ित थी। आज मृतक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। इस बीच आसपास के सैकड़ों ग्रामीण उसके घर पहुंचे। इसके बाद परिवार और दूसरे पक्ष के बीच जमकर विवाद शुरू हुआ। स्थिति बिगड़ती देख भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया गया। बताया जा रहा है मृतका के परिवार ने 7 साल पहले विशेष समुदाय के धर्म को अपना लिया है, जिसकी वजह से उनकी ग्रामीणों के साथ विवाद की स्थिति बनी है। मृतका का पार्थिव देह की कफन दफन की प्रक्रिया को सम्पन्न नहीं किया गया है। मृतका का शव अभी भी घर के आंगन में रखा हुआ है। हालांकि पुलिस ने बढ़ते विवाद को कंट्रोल किया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद शव का कफन दफन किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि सुबह से पुलिस की टीम यहां मौजूद है।

कृषि मंत्री ने प्रदेशवासियों को पोला तिहार की दी शुभकामनाएं

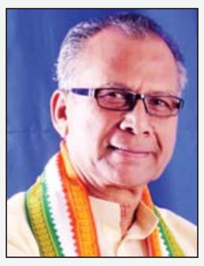

दुर्ग। कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खेती-किसानी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रतीक पोरा तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। पोरा तिहार की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में श्री साहू ने कहा है कि पोरा तिहार हमारे जीवन में खेती-किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। यह छत्तीसगढ़ की परम्परा, संस्कृति और जन-जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सुबह से किसानों द्वारा बैलों को नहलाकर पूजा अर्चना कर कृषि कार्य के लिए दुगने उत्साह से जुटने का प्रण लेते हैं। गांवों में छोटे बच्चे भी मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति से जुड़ा पोरा तिहार युवा पीढ़ी को पशुधन संवर्धन और संरक्षण की प्रेरणा देता है।

डिवाइडर से टकराकर गड्ढे में गिरी अनियंत्रित कार

कोरबा। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर के पास मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकराते हुए गड्ढे में गिर गई। हादसे में दो युवक घायल हुए हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, कार की रफ्तार तेज थी। जिस वजह से वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गड्ढे में गिर गई। कार में दो युवक फंस गए। हादसे होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला। जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस की दो गई। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी आज रायगढ़ में, कई मार्ग रहेंगे बंद

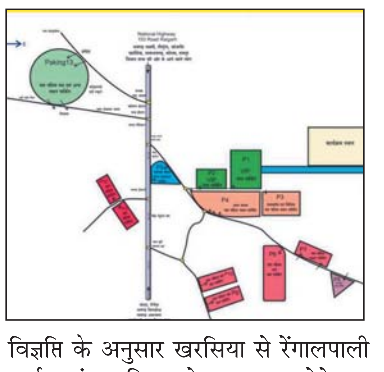

रायगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरूवार एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे है, जहां कोडातराई हेलीपैड में आयोजित कार्यक्रम में शिकरत करेंगे और आमसभा को संबोधित करेंगे। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई जिलों से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आमजन बड़ी संख्या में आएंगे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई मार्गो को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है। वहीं सुरक्षित मार्ग एवं पार्किंग व्यवस्था के लिये यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा मार्ग डायवर्सन पॉइंट, मार्ग प्रतिबंधित पॉइंट एवं वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था निर्धारित किया गया है। इस दौरान एनएच 53 के अलावा अन्य मार्गो से रायगढ़ में प्रवेश करने वाले सभी भारी वाहन सुबह 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक प्रवेश निषेध रहेगा।

रायगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार खरसिया से रेंगालपाली मार्ग एवं खरसिया से छातामुड़ा होते हुए सारंगढ़ मार्ग भारी वाहनों के आवागमन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों के वाहनों के पार्किंग हेतु 13 पार्किंग स्थलों का निर्धारण किया गया है। कार्यक्रम स्थल के समीप बनाये गये पार्किंग 01 एवं 02 वीवीआईपी तथा पार्किंग नं0 03 शासकीय वाहन एवं पास धारित मीडिया पार्किंग होगी। शेष पार्किंग 04 से 13 तक आमजन के लिये निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम में रामपुर, कोरबा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, खरसियां, जांजगीर, सक्ती विधानसभा की ओर से आने वाली वाहनें रायगढ़ के छातामुड़ा चौक से होते हुए सहदेवपदली पटेलपाली होकर कोडातराई पहुंचकर हाई स्कूल कोडातराई के पीछे स्थित पार्किंग नं0 13 में पार्क होंगी। बिलाईगढ़, सारंगढ़, चन्द्रपुर, पामगढ़, अकलतरा से आने वाली वाहनें बड़े भंडार, सूपा, चिखली, तेतला होते हुए ग्राम सुर्री के पार्किंग स्थल 09, 10 एवं कोडातराई के पार्किंग स्थल 11 एवं 12 पर पार्क होंगे।

बसना, सराईपाली, बरमकेला, सरिया की ओर से आने वाली वाहनें सूरजगढ़, पंडिग़ांव, मचिदा, ओडेकेरा, पुसौर, तड़ोला, झारमुड़ा होकर ग्राम हुए ग्राम सुर्री एवं कोडातराई के पार्किंग स्थल 6, 7 एवं 8 पर पार्क होंगी। इसी प्रकार सभी तरफ से आने वाली दो पहिया वाहनें कोड़ातराई के भागवत मैदान पार्किंग नं0 05 में पार्क होंगी। सभी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले पार्टी पदाधिकारीयों की चार पहिया वाहने कोडातराई कार्यक्रम स्थल पर पुसौर रोड स्थित बिजली विभाग के कालोनी की ओर बनाये गये कोडातराई पार्किंग नं. पी 4 में पार्क होंगी। इन डायवर्सन पॉइंट, प्रतिबंधित मार्ग एवं पार्किंग स्थलों की जानकारी आमजन, वाहन चालकों तथा ट्रांसपोर्टर को दिये जाने हेतु ट्रेफिक पुलिस रायगढ़ द्वारा प्रेस नोट जारी कर निर्धारित किए गए रूट प्लान का पालन कर सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में यातायात पुलिस का सहयोग प्रदान करने की अपील किया गया।

गड्ढों की मरम्मत के नाम पर एनएच में डाला मुरुम, भाजयुमो ने जताया विरोध

धमतरी। धमतरी शहर सहित आसपास की सड़कों का बुरा हाल है, चाहे वह नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे। इन सड़कों में एक फीट से दो फीट तक के गड्ढे हैं जिसके कारण शहर व आसपास की सड़कों में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। वहीं प्रशासन द्वारा रोड के गड्ढों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां नेशनल हाईवे रोड के गड्ढों में डामर डालने की जगह मुरूम डाल दिया गया। जिसको लेकर भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी के नेतृत्व में भाजयुमों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 30 में उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही सड़क में मुरूम डालने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी का कहना है कि जब से छत्तीसगढ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से प्रदेश में सड़कों का हाल बेहाल है। वहीं जर्जर सडकों की वजह से आए दिन सडक दुर्घटना में मौत हो रही है। सड़कों की बदहाल व्यवस्था को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन, चक्काजाम किया गया है लेकिन शासन-प्रशासन द्वारा कभी रोड में गिट्टी कभी मिट्टी कभी मुरुम डलवा कर खानापूर्ति ही किया गया है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि अगर जल्द सड़क के गड्ढों को नही भरा जाता तो आने वाले दिनों में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा।

कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया रेल रोको आंदोलन

रायपु। मोदी सरकार द्वारा लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किये जाने और ट्रेनों की लेटलतीफी के विरोध में तथा यात्री ट्रेनों की सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन प्रदेश के सभी जिलों बालोद, कांकेर, कोंडागांव, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जशपुर, कबीरधाम, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनादगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़, मोहला-मानपुर, सक्ति,मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी- भरतपुर, कोरबा, बीजापुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में किया।

इस अवसर पर कांग्रेस ने रेलमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में कहा गया कि पिछले तीन वर्षो से देश की रेल सुविधाएं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यात्री ट्रेनों की बिना कारण बताये रद्द कर दिए जाने का फरमान जारी कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ो यात्री ट्रेनों को अनेको बार महीनो तक के लिए रद्द किया गया है। महीनो पहले यात्रा की योजना बना कर रिजर्वेशन करवाने वाले यात्री रेलवे की इस मनमानी से परेशान होते है। त्योहारों छुट्टियों शादी ब्याह के सीजनों मे रेल्वे बिना बताए बिना कारण के यात्री ट्रेनों को रद्द कर देती है। रेल्वे द्वारा ट्रेनों को रद्द किये जाने का कारण मेंटेनेंस बताया जाता है। जबकि उन्ही ट्रेको पर यात्री ट्रेनों से 50गुना अधिक क्षमता की मालवाहक ट्रेनों को चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कोयले का परिवहन कर दूसरे प्रदेश को भेजने के लिए भी छात्तीसगढ़ की यात्री सुविधाओं को बाधित किया गया।

रेल्वे द्वारा जिस प्रकार से यात्री ट्रेनों के संचालन मे लगातार कोताही बरती जा रही उससे स्पष्ट हो रहा की रेल्वे यात्री सुविधाओं की अपेक्षा मालवाहक गाड़ियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही, यह जानबूझ कर किया जाने वाला षड्यंत्र है ताकि जनमानस मे रेल अलोकप्रिय हो और मोदी सरकार रेलवे को निजी हाथो विशेषकर अडानीसमूह को सौप सके रेल देश के नागरिकों की सबसे सुलभ और लोकप्रिय सुविधा है आजादी के पहले और बाद मे भी सभी सरकारों नें घाटा उठा कर भी जनहित मे रेल्वे का संचालन अनवरत जारी रखा। रेल्वे को बेचने का कोई भी प्रयास देश की जनता के साथ धोखा है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी।

कांग्रेस पार्टी मांग करती है की केंद्र सरकार यात्री ट्रेनों को नियमित चालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें साथ ही यात्री सुविधाओं विकलांग, बुजुर्ग, रिटायर्ड, सैनिकों, छात्रों, बच्चों को पूर्व में मिलने वाली रियायते बहाल की जाए तथा रेलवे के निजीकरण के षड्यंत्र पर तत्काल बिराम लगे।

प्रदेश कांग्रेस नें रेल्वे के द्वारा महामंत्री प्रभारी श्री मलकीत सिंह गेंदु को दिए वार्ता के प्रस्ताव को ठुकराया जनहित मे आंदोलन किया गया।13 सितंबर को सभी जिलों मे होगा रेल रोको आंदोलन मे कांग्रेसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए।

पिछला चुनाव जहां हारे इस बार नए चेहरे की तैयारी में हैं कांग्रेस

रायपुर। चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर पार्टियां फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। कांग्रेस ने इस बार 75 प्लस का टारगेट रखा है। पार्टी के जिम्मेदार सूत्रों की माने तो इस बार 40 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है इसलिए कि भाजपा भी अधिकांश सीटों पर नए चेहरे ला रही है। वहीं बड़ी बात यह भी सामने आ रही है जिन 19 सीटों पर चुनाव पिछली बार हारे थे वहां इस बार पुराने चेहरों को मौका नहीं दिया जायेगा क्योकि जब लहर में वे नहीं जीत पाये तो अब क्या गारंटी?इसलिए 50 वर्ष से कम उम्र, युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय उन नेताओं को मौका दिया जाएगा, जिनकी चुनाव जीतने की संभावना है। कांग्रेस ने टिकट के लिए ब्लाक स्तर पर आवेदन लिया था। यहां से आए 2,790 आवेदनों की छंटनी के बाद 273 नाम पैनल में शामिल किए गए हैं। प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी अब इन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पैमाने पर कसने का काम कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। टिकट तय करने वाली सभी कमेटियों ने माना कि जब प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, उस दौर में हारे नेताओं को मौका देना खतरे से खाली नहीं है। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, वहां दो से तीन दावेदार काफी मजबूत स्थिति में हैं। 90 में से 40 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे, इनमें 19 वो सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस हारी और 21 वो सीटें है, जहां कांग्रेस के विधायक हैं। इसीलिए टिकट घोषणा में कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। जहां पार्टी पिछला चुनाव हारी थी उनमें रायपुर दक्षिण, राजनांदगांव, कुरुद, बिल्हा, जांजगीर-चांपा, धमतरी, वैशाली नगर, कोटा, मुंगेली, लोरमी, बेलतरा, मस्तुरी, पामगढ़, जैजैपुर, अकलतरा, रामपुर, भाटापारा, बलौदाबाजार, बिंद्रानवागढ़ विधानसभा शामिल हैं।

कोंडागांव से कांग्रेस किसे देगी टिकट, सिटिंग विधायक को झेलनी पड़ रही नाराजगी

कोंडागांव। हाल ही में पीसीसी चीफ से मंत्री बने मोहन मरकाम का टिकट इस बार कट सकता है। कोंडागांव के कांग्रेस कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। पार्टी आलाकमान से मोहन मरकाम के बदले किसी और आदिवासी कांग्रेस नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं।

सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता आए दिन रायपुर पहुंचकर विधानसभा चुनाव में मोहन मरकाम को टिकट न देकर किसी दूसरे नए चेहरे को टिकट देने की डिमांड कर रहे हैं। पीसीसी संयुक्त महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोंडागांव के कई कांग्रेस कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे थे। वहां सभी ने एक सुर में मोहन मरकाम का विरोध जताया।

कांग्रेसियों ने मोहन मरकाम का विरोध करते हुए किसी नए चेहरे को कोंडागांव से टिकट देने का आग्रह किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे कैलाश पोयाम, और वर्तमान में सरपंच हेमलाल वट्टी, सरपंच दशरथ नेताम का नाम आगे किया। कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखते हुए आलाकमान ने भी सर्वे कर रिजल्ट के आधार पर कैंडिडेट को टिकट देने का आश्वासन दिया है।

पीसीसी संयुक्त महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने कहा बीते तीन-चार सालों से जब से मोहन मरकाम पीसीसी चीफ रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे ना ही जरूरत पड़ने पर कभी किसी का फोन उठाते थे। वह लगातार क्षेत्र के कार्यकर्ताओं व जनता को नेगलेक्ट करते रहे हैं।

भाजपा ने किया हराने का दावा

मोहन मरकाम का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध को भाजपा ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा ने बताया कि कांग्रेस कोंडागांव से किसी को भी टिकट दे दें। उसकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा मोहन मरकाम भले ही पिछले दो बार विधायक रहे हैं। लेकिन दोनों बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी है। जीत-हार में वोटों के अंतर का प्रतिशत बहुत कम रहा है। क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया है। पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में भी कोंडागांव से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार लता उसेंडी बहुत कम वोटों से हारी थी। वह भी इसलिए की कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे किए और मोहन मरकाम ने अपना स्वयं का व्यक्तिगत एक घोषणा पत्र जारी किया था जिससे जनता भ्रमित हुई थी और उन्हें वोट दिया। इस बार यदि मोहन मरकाम को टिकट मिलता है तो जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी।

सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस आलाकमान पहले ही ये साफ कर चुका हैं कि इस बार काम करने वाले और जिताऊ नेता को ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता और प्रभारी बार बार ये कह रहे हैं कि फील्ड से मिले रिजल्ट के आधार पर ही किसी भी दावेदार को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में मोहन मरकाम के खिलाफ उन्हीं के क्षेत्र से कांग्रेसियों की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है।

बस्तर में 16 को अरविंद केजरीवाल करेंगे 10वीं गारंटी का ऐलान

भाजपा और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी का फोकस बस्तर संभाग पर

रायपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आ रहे हैं। बस्तर के जगदलपुर में दोनों मुख्यमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान केजरीवाल आदिवासियों और किसानों के लिए 10वीं गारंटी का भी ऐलान करेंगे।

19 अगस्त को रायपुर में आयोजित सभा के दौरान केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 9 गारंटी का ऐलान उस समय किया गया। आदिवासी और किसानों के लिए 10वीं गारंटी रखी गई। जिसे केजरीवाल ने अगली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने के दौरान ऐलान की बात कही। अरविंद केजरीवाल का 3 महीने में यह छत्तीसगढ़ का तीसरा दौर होगा। इससे पहले केजरीवाल 2 जुलाई को बिलासपुर दौरे पर आए थे।

भाजपा और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी का फोकस भी बस्तर संभाग है। इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी बस्तर से ही आते हैं। ऐसे में 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल का जगदलपुर द्वारा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केजरीवाल की 9 गारंटी

बिजली- छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिल्ली और पंजाब के बाद 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली देंगे। नवंबर तक के पुराने बकाया बिजली बिल माफ कर देंगे। **शिक्षा**- सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट और गुंडा गर्दी बंद करवाएंगे। कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा। **स्वास्थ्य**- छत्तीसगढ़ में हर गांव और गली में मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे। सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे और इलाज मुफ्त होगा। **रोजगार**- छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। हर बेरोजगार को 3000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरी देंगे। **महिलाओं को भत्ता**-18 साल से अधिक उम्र की महिला को प्रति महीने 1000 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। **तीर्थ यात्रा**-छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, जेब से एक पैसा खर्च नहीं होगा। **भ्रष्टाचार मुक्ति**- छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा आएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर में काम करवाने नहीं जाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र घर बैठे बन जाएंगे। **शहीदों का सम्मान**- ड्यूटी पर काम करने वाले जवान, छत्तीसगढ़ के जवान को शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। **सरकारी कर्मचारियों को नियमित**- छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।

भारत जोड़ो सम्मेलन आज, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आएंगे

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर कल रायपुर आ रहे है, जहां पं. दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम आयोजित भारत जोड़ो सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, फूलोदेवी नेताम राज्यसभा सांसद, चंदन यादव सहप्रभारी सहित छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, जयसिंग अग्रवाल उपस्तिथ रहेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ी को पूरे देश मे अल्पसंख्यको की बुलंद आवाज़ के रूप में जाना व माना जाता है, राज्यसभा सांसद के रूप में भी इमरान प्रतापगढ़ी का एक अलग ही अंदाज रहा है, वें अपने शायराना अल्फाजों से देश के मज़लूमो की आवाज़ उठाते हुए राज्यसभा में सत्ता पक्ष को लगातार परेशान करते नजर आते हैं.।

मुख्यमंत्री भूपेश पर विजय बघेल का हमला

- **दूसरों को मारने वाला सांड भूपेश बघेल,मैं दुलार करवाने वाला बछड़ा,पाटन की जनता कसेगी नकेल - विजय बघेल**

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं।वैसे वैसे बयानों के तीर नेताओं की तरकश से छूट रहे हैं। ताजा बयान बीजेपी के घोषणापत्र समिति के संयोजक और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल का है।जिन्होंने सीएम भूपेश बघेल को दो सींग वाला मारने वाला सांड बताया है। विजय बघेल ने अमरजीत भगत के सांड और बछड़े की लड़ाई वाले बयान पर पलटवार भी किया।इस दौरान विजय बघेल ने टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच हुई आपसी लड़ाई का भी जिक्र किया।

बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा।इस दौरान बघेल ने कहा कि अति का अंत होता है। यहां के विधायक का दादागिरी दिख रहा है। उसके खुद के उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। विधायक कह रहे हैं कि मेरी हत्या करने की साजिश महाराजा साहब कर रहे हैं। राक्षस लोग खुद ही आपस में लड़ते हैं। क्योंकि समझदार लोग आपस में नहीं लड़ते। विजय बघेल ने पाटन से मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर भी तंज कसा।अमरजीत भगत ने विजय बघेल और सीएम भूपेश के बीच मुकाबले को सांड और बछड़े की लड़ाई बताया था।जिस पर विजय बघेल ने हमला करते हुए कहा कि बछड़े को लोग प्यार दुलार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। मुझे उसी तरह प्यार करती है। लेकिन सांड कौन है ये सब जान गए हैं। विजय बघेल ने कहा एक होता है मारने वाला सांड दो बड़े सींग वाले। दूसरे सांड भी डरते हैं मारने वाले सांड के बीच में आने से। दूर से देखते हैं। सबको मार कर खाने वाला सांड ही भूपेश बघेल है। उसको नकेल लगाने का काम पाटन की जनता को दिया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पाटन की जनता उसको पटकेगी और नकेल लगाएगी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा से उम्मीदवारी की है।इस विधानसभा से किसी दूसरे दावेदार ने नामांकन नहीं भरा है।इसलिए ये तय माना जा रहा है कि विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच चुनावी जंग होगी।लेकिन इस जंग से पहले ही दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बयानबाजी से माहौल और भी गर्मा दिया है।मौजूदा समय में विजय बघेल घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ किस तरह की रणनीति बनाकर मैदान में उतरती है।

सिर्फ 61 पदों के लिए 52 हजार आवेदन कैसे जमा हुए, भाजपा ने उठाया सवाल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोजगार देने के चाहे जितने झूठे दावे करके छत्तीसगढ़ को बरगलाने की नाकाम कोशिश करे, सच्चाई खुद-ब-खुद सामने आकर प्रदेश सरकार के दावों को खोखला साबित कर देती है। सरकार के दावों की पोल एक बार फिर काँकेर में खुली है, जहाँ कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग के तीन माह पहले निकली वेकेंसी में मात्र 61 पदों के लिए लगभग 52 हजार आवेदन जमा हुए हैं। इनमें से केवल भृत्य के 11 पदों के लिए लगभग 25 हजार आवेदन हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक श्रीमती साहू ने कहा कि जब प्रदेश सरकार लाखों युवकों को रोजगार देने का ढिंढोरा पीटती प्रदेशभर में झूठ का रायता फैला रही है तो फिर वह यह भी बताए कि सिर्फ 61 पदों के लिए 51,659 आवेदन कैसे जमा हो रहे हैं? इनमें से 24,874 आवेदन तो केवल भृत्य के 11 पदों के लिए जमा हुए हैं यानि हर एक पद के लिए 2200 आवेदन जमा हुए है ! इनकी गिनती और ऑनलाइन एंट्री करने में 19 कर्मचारी तीन महीने से लगे हैं। प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में कतई ईमानदार नहीं रही है।

इस वर्ष के बजट में इसके लिए सिर्फ 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जबकि कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में 10 लाख नौजवानों को या तो रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कांग्रेस और उसकी राज्य सरकार साढ़े 4 साल बाद युवाओं के भारी दबाव के चलते बेरोजगारी भत्ता देने का दिखावा कर रही है और उसमें भी बेरोजगारी के जटिल मापदंड तय करके लाखों युवकों को बेरोजगारी की केटेगरी से बाहर कर दिया और अब कुछ हजार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देकर ढिंढोरची बनी फिर रही है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक श्रीमती साहू ने कहा कि विधानसभा में प्रदेश के रोजगार मामलों के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5 प्रतिशत ही है लेकिन संख्या नहीं बता सकते। जबकि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजगार चाहने वाले 18.78 लाख युवकों ने पंजीयन कराया है। इन दोनों आँकड़ों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि या तो छत्तीसगढ की आबादी तीन करोड़ नहीं, बल्कि 36 करोड़ है; या फिर बेरोजगारी दर के 0.5 प्रतिशत होने का दावा और लिखित उत्तर, दोनों झूठे हैं।

मरीजों और डॉक्टरों के लिए लागू होगा बायोमीट्रिक सिस्टम

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इम्पैनलमेंट की पात्रता में बदलाव किया जाएगा। इन शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में न्यूनतम 50 बिस्तर वाले दो वर्ष पुराने अस्पताल अनुबंध के लिए पात्र होंगे। प्रदेश के गैर-अधिसूचित विकासखंडों में न्यूनतम 30 बिस्तर और एक वर्ष पुराना तथा अधिसूचित विकासखंडों में कम से कम छह माह पुराने 15 बिस्तर वाले अस्पतालों को इम्पैनलमेंट की पात्रता होगी। सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट के लिए अलग से नए मापदंड तय किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी और सीजीएमएससी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मौजूद वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसके निर्देश दिए। बैठक में शासकीय योजनाओं के तहत इलाज की सुचारू व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने तथा उपचार के क्लेम के अस्पतालों को भुगतान में तेजी लाने मरीजों और डॉक्टरों के लिए जीपीएसयुक्त बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पोला तिहार की दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से किसान भाइयों को पारंपरिक पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। पोरा तिहार की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में श्री बघेल ने कहा है कि पोला तिहार छत्तीसगढ़ की परम्परा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा पर्व है। यह हमारे जीवन में खेती-किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। इस दिन घरों में उत्साह से बैलों और जाता-पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर को धन-धान्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना की जाती है। श्री बघेल ने कहा कि तीज-त्यौहार हमारी संस्कृति और परम्पराओं का संवाहक होते हैं। यह हमारी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। पोला के दिन मिट्टी के बर्तन और बैलों से खेलकर बच्चे अनजाने ही अपनी मिट्टी और उसके सरोकारों को जुड़ते चले जाते हैं। श्री बघेल ने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध संस्कृति का परिचय कराएं और उसके संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करें।

यादव व जांगिड़ कल आएंगे

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव गुरूवार को नियमित विमान सेवा द्वारा दोपहर 1.45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस से राजीव भवन के लिये रवाना होंगे। दोपहर 3.10 बजे राजीव भवन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं बैठक में शामिल होंगे एवं रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगिड गुरूवार को नियमित विमान सेवा द्वारा शाम 5.10 बजे रायपुर पहुंचेंगे एवं मुख्यमंत्री निवास के लिये रवाना होंगे। शाम 5.30 बजे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में शामिल होंगे एवं रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे।

स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल समाप्त

रायपुर। पिछले माह अगस्त की 21 तारीख से हड़ताल पर चल रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज सरकार की ओर से मिले सकारात्मक व ठोस आश्वासन के बाद अपना हड़ताल स्थगित कर दिया है। सरकार की ओर से गए प्रतिनिधि मंडल ने हड़तालियों की बात को गंभीरता से सुना और अपना प्रस्ताव रखा जिस पर आपसी सहमति बनी और जनहित में हड़ताल समाप्त हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों के संगठन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रतिनिधिमंडल को इस सहयोगात्मक कदम के लिए धन्यवाद भी दिया। फेडरेशन के पदाधिकारी टारजन गुप्ता , डॉक्टर इकबाल , डॉक्टर रीना राजपुत , श्रीमती सुमन शर्मा , अंशिला बेस , डॉक्टर हीरासिंग लोधी,भूपेंद्र सोनी,श्रीमती देवाश्री साव एवम् समस्त सदस्यों ने जारी बयान में कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों का आंदोलन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधमंडल द्वारा दिए आश्वासन पर 24 वे दिन स्थगित हो गया है।स्वास्थ्यकर्मियों (डॉक्टर्स,स्वाथ्य संयोजक, नर्सेज) का 21 अगस्त से शुरू हुआ था जिसमे पहली बार किसी आंदोलन में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल हड़ताल स्थल में आकर कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए आंदोलन को स्थगित कराया। साथ ही हड़ताल स्थगित होते ही मुख्यमंत्री की के निर्देश में बर्खास्तगी,निलंबन की बहाली का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर राकेश गुप्ता (अध्यह,कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ),सुशील शुक्ला (कांग्रेस प्रवक्ता),धनंजय सिंह ठाकुर (कांग्रेस प्रवक्ता)अजय साहू शामिल थे। संघ के प्रांतीय संयोजकों ने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए और जनहित में आज हड़ताल स्थगित करने का घोषणा कर दिया।

विधायक उपाध्याय ने दिलाया ताराचन्द के परिवार को 4 लाख मुआवजा राशि

रायपुर। कुछ माह पूर्व खमतराई के रहने वाले ताराचंद साहू की विद्युतीय हादसे में मौत हो गई थी। मृत्यु की सूचना जब विधायक विकास उपाध्याय को मिली,उन्होंने शोक जताते हुए मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने खमतराई बिजली ऑफिस के अधिकारी को निर्देशित किया। उसी मुआवजे की पूर्ण राशि चेक के माध्यम से 4 लाख रूपये मृतक की पत्नी सेवती साहू को संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे की उपस्थिति में प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि राजभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, इसका स्वरूप समावेशी है। इसकी लिपि देवनागरी विश्व की सबसे पुरानी एवं वैज्ञानिक लिपियों में से है। यह निरंतर प्रवाहमान भाषा है। हिन्दी का शब्द भंडार एक तरफ संस्कृत से तो दूसरी तरफ अनेक देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिन्दी के सहज-सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। हिन्दी के गुण उसे भाषा के दर्जे से ऊपर एक संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। हिन्दी भाषा आज जन-जन की भाषा बन गई है। श्री बघेल ने कहा है कि प्रसिद्ध रचनाकार श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है कि %%निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल'' मतलब मातृभाषा की उन्नति बिना, किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। सभी राजभाषा के गौरव और महत्व को और आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित भाव से कार्य करें।

भारत ने किया चीनी साजिशों का पर्दाफाश

संतोष पाठक

भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ जी-20 का सफल शिखर सम्मेलन, भारत के लिए कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। जी-20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन कर भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अब यह भारत वह भारत नहीं है जिसे दुनिया खासतौर से यूरोपीय और अमीर देश सांप-सपेरों के देश के रूप में देखते थे, बल्कि यह नया भारत न केवल उनके साथ खड़ा है बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी अब इसी भारत के पास है। रूस यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई को लेकर जिस तरह से जी-20 में शामिल देश दो खेमों में बंट गए थे उसे देखते हुए यह आशंका जताई जाने लगी थी कि जी-20 के सम्मेलन में आम सहमति से कोई घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया जा सकेगा। एक तरफ जहां चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भारत ना आकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह दिल्ली में होने जा रहे जी-20 सम्मेलन को बहुत ज्यादा तवज्जो या यूं कहें कि ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधि के रूप में जी-20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बिना किसी लाग-लपेट के सख्त भाषा में स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि अगर जी-20 के साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध पर रूस के पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया तो वह इसे नामंजूर कर देगा। ऐसे में असफलता की प्रबल आशंका के साथ जी-20 का यह सम्मेलन शुरू हुआ और भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ जहां अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों को साधा तो वहीं दूसरी तरफ रूस को भी तैयार किया। दिल्ली घोषणापत्र की शब्दावली को बदला गया और आखिरकार जी-20 के सभी देशों ने इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। बाद में कई देशों ने यह माना कि यह सब भारत की सफल कूटनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण ही संभव हो पाया। लेकिन दिल्ली का यह सम्मेलन सिर्फ इस लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं रहा बल्कि भारत ने जी-20 का सफल आयोजन कर अरब से लेकर अफ्रीका तक चीन की कुटिल रणनीति का पर्दाफाश भी कर दिया। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि चीन ने अपनी व्यग्रता में खुद ही अपनी भावना को दुनिया के सामने ला दिया कि वह दुनिया में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया, आतंकवाद के खात्मे, क्षेत्रीय अखंडता, देशों की स्वतंत्रता, अफ्रीकी गरीब देशों के विकास और यातायात के साधनों के विकास को लेकर एक ऐसी सोच रखता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका ही फायदा हो और इसलिए दिल्ली का यह सम्मेलन इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर चीन जैसे ताकतवर देश को भी अलग-थलग कर दिया। भारत की पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से दिल्ली की बैठक में जी-20 का विस्तार कर इसमें अफ्रीकी संघ को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पीएम मोदी ने बैठक की शुरुआत में ही सदस्य देशों के सामने ग्लोबल साउथ के प्रमुख ब्लॉक अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा जिसको सभी नेताओं ने स्वीकार कर लिया। अफ्रीकी देशों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए भारत को धन्यवाद भी कहा।

मोदी का विजन, शाह का सुपरविजन

अभिनय आकाश

नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सेनापति और मोदी की आंख, कान और जुबान समझे जाने वाले अमित शाह मोदी 2.0 की सरकार में 30 मई को अमित शाह पहली बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो गए। शपथ के बाद पीएम मोदी ने उन्हें गृह मंत्रालय की कमान सौंपकर यह जता दिया कि मोदी सरकार 2 में उनकी हैसियत नंबर दो की होगी। इसके ठीक 2 बरस बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जब नए मंत्री शपथ ले रहे थे उससे ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाने की घोषणा कर दी। । कहा गया कि ये मंत्रालय देश में सहकारी समितियों के उत्थान के लिए काम करेगा और सहकारी समितियों को मजबूत करेगा। किसी नए मंत्री को इसकी जिम्मेदारी देने की बजाए देश के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई। स्वतंत्रता-पूर्व युग से ही सहकारिता भारत की आर्थिक और सामुदायिक प्रगति में एक अपरिहार्य सरीखा ही रही है। स्वदेशी संसाधनों को एकत्रित करके और स्वयं-स्थाई नेटवर्क का निर्माण करके भारत की विविध सहकारी समितियों ने कृषि, बैंकिंग, डेयरी, आवास और कारीगर व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वित्तीय एकीकरण और जमीनी स्तर पर मुक्ति को उत्प्रेरित किया है। हालाँकि, दशकों से अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यावसायिकता की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं और खंडित प्रयासों ने इस क्षेत्र को जकड़ लिया है, जिससे इसकी संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षमता का निकलकर नहीं आ पा रही है। इसे सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने 2021 में एक नया, समर्पित सहयोग मंत्रालय बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए अमित शाह को चुना, जिन्हें अक्सर उनके %दाहिने हाथ% के रूप में चित्रित किया जाता है। सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े पैमाने पर परिवर्तन को इंजीनियर करें। पहली नज़र में इस अप्रत्याशित चाल ने कई पर्यवेक्षकों को स्तब्ध कर दिया। हालाँकि, कड़ी परीक्षा के बाद, अमित शाह स्पष्ट रूप से भारत की सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के महत्वपूर्ण मिशन का समर्थन करने वाले इष्टतम नेता के रूप में उभरे हैं। ऐसे में आज का एमआरआई हम सहकारिता विभाग पर करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अमित शाह को ही क्यों चुना गया?

अमित शाह के पास सहकारी समितियों के साथ सहयोग का एक शानदार इतिहास है, खासकर भारत में सबसे सशक्त सहकारी क्षेत्रों में से एक्ष गुजरात में।

एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उनके गुजरात कार्यकाल के दौरान, राज्य ने भाजपा के तत्वावधान में सहकारी बैंकों और डेयरी सहकारी समितियों का एकीकरण देखा। एक व्यावहारिक प्रशासक के रूप में शाह ने सहकारी समितियों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जमीनी हकीकतों और जटिलताओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। यह अनुभवात्मक समझ राष्ट्रीय नीतियों और विनियमों को तैयार करने में अमूल्य हो सकती है जो वास्तव में जमीनी जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप हों।

राजनीतिक जगत में शाह को व्यापक रूप से भाजपा के %चाणक्य% के रूप में वर्णित किया जाता है। जिस भाजपा के बारे में कहा जाता था कि %बैठक, भोजन और विश्राम... भाजपा के यह तीन काम% शाह ने इस धारणा को भी ध्वस्त कर दिया। वह खुद तो मेहनत करते ही हैं, कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करते हैं। 2014-2019 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें पूरे भारत में भाजपा के ऐतिहासिक प्रभुत्व और उसकी शानदार चुनावी जीत के प्राथमिक वास्तुकार के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। विवेकपूर्ण तरीके से रणनीति बनाने, संगठनात्मक जटिलताओं को सुलझाने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए यह संकाय काफी फायदेमंद है क्योंकि शाह क्षेत्रीय सहकारी राजनीति की भूलभुलैया को नेविगेट करते हैं। उनकी कुशल रणनीति महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विशेष रूप से प्रासंगिक होगी, जहां सहकारी समितियों का गहरा राजनीतिक प्रभाव है।

हालाँकि सहकारी समितियाँ पेशेवर वित्तीय और नियामक संस्थाओं की तरह लग सकती हैं, उनकी मौलिक प्रेरणा ग्रामीण स्तर पर जमीनी स्तर की भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता से प्राप्त होती है। ग्रामीण भारत में जोरदार राजनीतिक अभियानों का नेतृत्व करने के बाद, अमित शाह जमीनी स्तर पर सामुदायिक लामबंदी को आंतरिक रूप से समझते हैं। भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने के साथ यह प्रवाह, नीचे से ऊपर की गतिशीलता और मानव संसाधन प्रबंधन लचीलापन शाह को अधिक से अधिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने और सहकारी समितियों में भागीदारी को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

2019 से गृह मंत्री के रूप में, अमित शाह ने कई निडर सुधारों का बीड़ा उठाया है, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भी शामिल है। उनकी दृढ़ प्रशासन साख, सिस्टम को तुरंत पुन॰ कॉन्फ़िगर करने की क्षमता और उपलब्धियों का ट्रैक रिकॉर्ड उनकी ताकत की सूची की आधारशिला हैं। नवोदित सहयोग मंत्रालय का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार एक समर्पित प्रशासनिक, कानूनी और नियामक वातावरण तैयार करना है। इस संस्थागत तंत्र को कुशलतापूर्वक बनाने के लिए शाह की मान्य प्रशासनिक समझ और सुधार-उन्मुख दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। मोदी शासन ने नए मंत्रालय के लिए अपना दृष्टिकोण %सहकार से समृद्धि% के रूप में व्यक्त किया है, जो सहयोग के माध्यम से समृद्धि का प्रतीक है। यह आदर्श वाक्य संक्षेप में बताता है कि कैसे सहकारी समितियों को भारत के विकास खाका के केंद्र में रहना चाहिए। सहकारिता मंत्री के रूप में पदभार संभालने से पहले भी, शाह ने सक्रिय रूप से शीर्ष सहकारी संस्थाओं और नेताओं के साथ बैठकें कीं ताकि उनके दृष्टिकोण को आत्मसात किया जा सके। यह सहकारी समितियों को मजबूत करने के शासन के घोषित दृष्टिकोण के प्रति उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जबकि कई सरकारी उद्यम सुस्त प्रगति के कारण लड़खड़ा रहे हैं, शाह ने पहले ही नवोदित मंत्रालय में जोरदार गति ला दी है। केवल 20 महीनों के भीतर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्थानों को पुनर्जीवित और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 20 से अधिक नवीन योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं। यह शाह के कार्य-उन्मुख नेतृत्व के सिद्धांत को दृष्टि से कार्यान्वयन तक तेजी से स्थानांतरित करने का उदाहरण देता है। पहलों के तेजी से कार्यान्वयन ने परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के मंत्रालय के गंभीर इरादे के बारे में हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाया है। समावेशन और सहयोगात्मक सिद्धांत के वास्तविक परिवर्तन के लिए सभी हितधारकों को साथ लेने और क्षेत्र के विशेषज्ञ इनपुट के अनुसार पहल को आकार देने की आवश्यकता है। इस दृढ़ विश्वास के अनुरूप, शाह ने मंत्रालय को नीतिगत सुधारों पर सलाह देने के लिए सभी स्तरों के सहकारी नेताओं को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर से नीचे की कार्यप्रणाली से हटकर, मंत्रालय आधार का गठन करते हुए प्राथमिक समाज स्तर पर भागीदारी और समावेशन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सहयोगात्मक नीति-निर्माण और जमीनी स्तर पर अभिविन्यास पर यह जोर शाह की सुधारवादी वंशावली को और अधिक मान्य करता है।

शाह न केवल राजनीतिक चतुराई बल्कि बहुआयामी विशेषज्ञता का भी योगदान देते हैं। उन्होंने गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का नेतृत्व किया है, और गुजरात राज्य सहकारी विपणन महासंघ जैसी विशाल सहकारी समितियों के बोर्ड में निदेशक रहे हैं। स्थानीय और राज्य दोनों स्तरों पर सहकारी समितियों के प्रबंधकीय और वित्तीय पहलुओं का यह अनुभव उन्हें समग्र दृष्टिकोण से सुसज्जित करता है। वह न केवल स्थानीयकृत सामाजिक गतिशीलता को समझते हैं बल्कि व्यापक शासन, नियामक और परिचालन चुनौतियों को भी समझते हैं।

कई सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से बैंकिंग और डेयरी में असंगत अंतर-राज्य नीतियों, नियमों और राजनीतिक उलटफेर के कारण अपने गृह राज्यों से परे विस्तार करने में बाधाओं का सामना करती हैं। एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में, जिसने भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं पर भाजपा के पदचिह्न को बढ़ाया है, शाह एक व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देते हैं। उनका अनुभव बहु-राज्य सहकारी समितियों के एकीकृत विस्तार को सक्षम कर सकता है और राज्य-स्तरीय ढांचे के बीच असमानताओं को दूर करके निर्बाध अंतर-राज्य संचालन की सुविधा प्रदान कर सकता है। शाह को सहकारिता मंत्री नियुक्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि उनका शासन सहकारी आंदोलन को मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देता है। शाह पीएम मोदी के सबसे करीबी विश्वासपात्रों और सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों में से एक हैं। यह शाह को राजनीतिक रूप से अनिश्चित क्षेत्र में निडर सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित अधिकार प्रदान करता है। प्रधानमंत्री का समर्थन विभिन्न हितधारकों को बड़े पैमाने पर सहकारी सुधारों के प्रति शासन की दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में भी आश्वस्त करता है। संक्षेप में, वास्तव में भारत की सहकारी समितियों को पुरातन प्रथाओं से लेकर हितों के टकराव तक अनगिनत समस्याओं ने घेर रखा है। इस अपरिहार्य क्षेत्र को इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बदलने के लिए गतिशील नेतृत्व के साथ-साथ जमीनी जरूरतों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होगी। सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह की नियुक्ति ने शुरू में पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

श्रोत्र आत्मा के आश्रित हैं तथा स्वयं पशुपति ब्रह्म श्रोत्र में प्रविष्ट होकर उन शिव को श्रवण शक्ति देते हैं। मन भी अपनी अन्तरात्मा में अभ्यस्त है एवं परब्रह्म परमेश्वर उसमें प्रविष्ट होकर, उस सत्त्व में स्थित होते हुए उसे नियम में रखते हैं और मनस्विता प्रदान करते हैं।

ऐसे ही वे परम ईश्वर समस्त इन्द्रियों को सचेष्ट करते हैं, परन्तु लोग उन ब्रह्म को जैसा बताते हैं अथवा कल्पना करते हैं, उससे वे महेश्वर सर्वथा भिन्न हैं। परब्रह्म परमेश्वर ही इन समस्त इन्द्रियों को अपने अनुकूल रूप प्रदान करते हैं एवं उनका नियमन भी करते हैं। इस कारण ये चक्षु, मन, वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ परमपिता परमात्मा के स्वयं प्रकाशतत्त्व (रूप) को प्राप्त नहीं हो सकत अर्थात् उनके ज्ञानरूपी प्रकाश को जानने में समर्थ नहीं हो सकतीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है कि परमात्मा अन्तः के विषयों से भिन्न (अलग) है, वह तर्क एवं प्रमाण के बिना ही उसे अपनी अन्तरात्मा द्वारा जानने का निरन्तर प्रयास करे, उसे यथार्थ रूप में परमात्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा ही परम प्रकाश स्वरूप है, जबकि वह माया महा अन्धकाररूप है। इसलिए प्रत्यगात्मा एवं माया की एकता किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। उसके तर्कों, प्रमाणों एवं अनुभव से ज्ञात होता है कि चैतन्यमय स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा में माया नहीं है। विद्या एवं अविद्या के विषय व्यावहारिक हैं, परमात्मा से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

तात्त्विक दृष्टि से यह सभी कुछ मिथ्या ही है। केवल एक तत्त्व ही वास्तविक सत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से जो भी कुछ जान पड़ता है, वह भी वैसे ही आभासित होता है। प्रकाश ही निरन्तर विद्यमान है। इस प्रकार यह अद्वैत ही है, अद्वैत ही इस प्रकार के प्रकाश के अभेद से कहा जाता है।

इस प्रकार से सर्वत्र सतत एक प्रकाश स्थित है। इसके सन्दर्भ में और अधिक कुछ कहने की अपेक्षा मौन ही उत्तम है। जिस मनुष्य को यह महान् ज्ञान स्वयमेव ज्ञात हो गया है, वह न जीव रूप है, न ब्रह्म है और न ही कुछ और है। उसका न कोई वर्ण है तथा वह आश्रम भी नहीं है। वह धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है, निषेध एवं विधि भी वह नहीं है। जब उसको सब कुछ ब्रह्ममय ही दृष्टिगोचर होता है, तब उसे इस दुःखादि भेद का आभास बिल्कुल नहीं जान पड़ता। परब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार से ज्ञान रखने वाला इस जीवादि स्वरूप वाले विश्व को देखते हुए भी नहीं देखता।

क्रमशः ...

पोला पर्व

पोला का त्यौहार भादों माह की अमावस्या को जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते है, उस दिन मनाया जाता है। यह अगस्त-सितम्बर महीने में आता है। इस वर्ष 14 सितंबर को यह मनाया जायेगा। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते है, विशेष तौर पर विदर्भ क्षेत्र में इसकी बड़ी धूम रहती है। वहां यह त्यौहार दो दिनों तक मनाया जाता है। वहां बैल पोला को मोठा पोला कहते हैं एवं इसके दुसरे दिन को तनहा पोला कहा जाता है।

विष्णु भगवान जब कान्हा के रूप में धरती में आये थे, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप मे मनाया जाता है। तब जन्म से ही उनके कंस मामा उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। कान्हा जब छोटे थे और वासुदेव-यशोदा के यहाँ रहते थे, तब कंस ने कई बार कई असुरों को उन्हें मारने भेजा था। एक बार कंस ने पोलासुर नामक असुर को भेजा था, इसे भी कृष्ण ने अपनी लीला के चलते मार दिया था, और सबको अचंभित कर दिया था। वह दिन भादों माह की अमावस्या का दिन था, इस दिन से इसे पोला कहा जाने लगा। यह दिन बच्चों का दिन कहा जाता है, इस दिन बच्चों को विशेष प्यार, लाढ देते है।

भारत त्योहार और उत्सवों का देश का है। ये त्योहार ना सिर्फ लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ते

हैं बल्कि ये अहसास भी कराते हैं इस धरती पर किसी एक चीज के होने के मायने क्या हैं। और जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी उसके लिए कुछ करने को आतुर रहते हैं, कई बार ये शुक्रिया, धन्यवाद, एहसानमंदी उत्सव के रुप में मनाई भी जाती है। ऐसा ही एक त्योहार है बैल पोला।

बैल पोला या बैलों की पूजा, खेती में किसानों के साथी, सारथी और उसके साथ कंधे से कंधामिलकर चलने वाले बैलों का त्योहार। अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए विख्यात छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये त्योहार किसान धूमधाम से मनाते हैं। किसानों के लिए ये गणेश उत्सव से कम नहीं होता। इस दिन किसान के घर का एक व्यक्ति व्रत रखता है। घर में तांबे के लोटे में कलश रखा जाता है। किसान बताते हैं, जिस हल से हम लोग बुवाई करते हैं, उसके नीचे जो लोहे का फाल लगा होता है उसे निकालकर उपर रख देते हैं, इसका मतलब है आज काम की छुट्टी है। बैलों की आरती होती है, उन्हें पोली नैवेद्य (चावल और दाल से बना विशेष व्यजंन) और फिर गुडवनी (गुड़ से बना व्यंजन) खिलाया जाता है, बैल पोली खिलाई जाती है, घर के लोग मिलकर बैलों को खेती में साथ देने के लिए धन्यवाद कहते हैं। कई लोग घर में पूजा करने के बाद गांव के मंदिर आदि में जाकर नारियल भी फोड़ते हैं। कई जगहों पर गांव के लोग अपने अपने बैलों को लेकर आते हैं, और एक अघोषित प्रतियोगिता होती है, कि किसके बैल ज्यादा अच्छे से सजाए संवारे गए हैं। इस प्रतियोगिता के लिए किसानों और कई बार उनके घरों में हल जोतने वाले कई महीनों और या दिन पहले से बैलों की अच्छे से सेवा शुरु कर देते हैं। वैसे तो ज्यादातर महाराष्ट्रीयन परिवारों में भादप्रद अमावश्या को ये त्योहार मनाया जाता है लेकिन बैलों से जुड़े वहां कई और त्योहार हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी बैल पोला ही मनाती है। बैलों की पूजा से जुड़ा एक त्योहार बेंदुर होता है जो जून के महीने में बुआई के दौरान मनाया जाता है। इस त्योहार में भी ऐसे ही बैलों को हल्दी लगाई जाती है उनकी उनकी पूजा होती है।

दिल्ली डिक्लरेशन मायने वन अर्थ, वन फैमेली, वन फ्यूचर

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देखा जाए तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी 20 सम्मेलन हर मायने में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है। भारत की मेजबानी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विजन का ही परिणाम रहा कि एक और जहां जी 20 का कुनबा बढ़ाने में भारत कामयाब रहा तो दूसरी और दिल्ली डिक्लरेशन को एक मत से स्वीकार कराने की बड़ी सफलता कूटनीतिक स्तर पर भारत की बढ़ती सक्रिय हिस्सेदारी और सोच समझ को दर्शाती है। कोई माने या ना माने पर अब यह साफ होता जा रहा है कि भारत आज अपनी बात मनवाने व दुनिया के देशों के सामने लोहा मनवाने में सफल रहने लगा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी 20 सम्मेलन में बने मसौदे पर दुनिया के देश एकमत नहीं हो पाये थे। रुस और चीन के प्रमुखों के नहीं आने और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद भारत दिल्ली डिक्लरेशन के सभी 83 बिन्दुओं को एक मत से पारित कराने में सफल रहा। यह सब तो तब है जब जी 20 के सभी देशों के पास बिन्दु विशेष पर वीटों करने के अधिकार हैं यह पहले के सम्मेलनों में देखा जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि जी 20 के सेशन वन फैमेली के दौरान दिल्ली डिक्लरेशन पर सर्वसम्मति की घोषणा से वन फैमेली का वास्तविक संदेश दुनिया के देश देने में सफल रहे हैं। सही मायने में यह दुनिया के देशों के वन फैमेली की दिशा में बढ़ता कदम है।

देखा जाये तो भारत के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और इसके साथ ही वन अर्थ, वन फैमेली, वन फ्यूचर का संदेश ही वसुधैव

कुटुम्बकम को चरितार्थ करता है। इसे काल चक्र का ही फेर कहा जाएगा कि जिस काल चक्र के सामने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी 20 के दिग्गजों की अगवानी कर रहे थे उस काल चक्र ने ही संदेश दे दिया कि भारत 2500 साल पहले भी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था तो आज भी वह दुनिया के देशों से किसी भी मायने में कम कर नहीं रह गया है। यों तो जी 20 का यह सम्मेलन कई मायनों में याद किया जाएगा तो लाख कमियां गिनाई भी जा सकती है पर इस सम्मेलन ने जो उंचाइयां छुई है उन्हें सालों याद रखा जाएगा। इस सम्मेलन की ही देन है कि अब जी 20 में 55 देशों के संघ अफ्रीकी यूनियन को स्थाई सदस्यता दिलाने में सफलता मिल गई है। यानी की जी 20 का कुनबा बढ़कर अब जी 21 हो गया है तो दूसरी और इसकी ताकत में भी बढ़ोतरी हुई है।

वैसे भी देखा जाए तो 1999 में जी 20 की स्थापना हुई तो आर्थिक सहभागिता एक प्रमुख ध्येय रहा। दुनिया के देशों की 85 फीसदी जीडीपी, 75 फसीदी वैश्विक व्यापार और दो तिहाई आबादी इस कुनबे की ताकत थी। अब अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने से इसकी ताकत और पहुंच और अधिक बढ़ गई है। बारी बारी से अध्यक्षीय जिम्मेदारी के बीच भारत की एक वर्ष की अध्यक्षीय अवधि जी 20 के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत द्वारा इस तरह की कार्ययोजना बनाई गई कि सभी अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चाएं तय की गई तो दूसरी और गंभीर चिंतन मनन हुआ। इसके साथ ही भारत के कोने कोने से सदस्य देशों को रुबरु होने का अवसर मिला वह अलग। यानी कि भारत के बारें में दुनिया के देशों के सामने समग्र तस्वीर रखी जा सकी। देश के 60 शहरों में जी 20 की बैठकें आयोजित हुई यहां तक कि कश्मीर में भी जी 20 की बैठक आयोजित कर एक संदेश देने का प्रयास किया गया। 200 घंटों की अथक मेहनत और करीब 300 बैठकों का परिणाम है दिल्ली डिक्लरेशन। सबसे बड़ी बात कि भारत ने सबके भरोसे की बात की और सबका भरोसा जीतना ही इसकी सबसे बड़ी सफलता माना जा सकता है।

कोरोना ने दुनिया के देशों के सामने एक अलग तरह के हालात रखें तो सोच और समझ में भी बदलाव आया है। हांलाकि कोरोना त्रासदी के बाद भी रुस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक आर्थिक संकट, आतंकवाद के नित नए रुप, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ने, अनियमित मानसून, तूफान और अनचाही बाढ़ जैसे हालात, समुद्री सतह का बढ़ना, केरेंसी को लेकर संकट जैसे अनेक संकट तेजी से उभरे हैं। दिल्ली डिक्लरेशन में इन सभी मुद्दों व चुनौतियों के प्रति गंभीरता दिखाई गई है। यहां तक कि सबसे अधिक मतभेद की संभावना रुस यूक्रेन युद्ध को लेकर होने के बावजूद डिक्लरेशन में युद्ध का विरोध, दुनिया के देशों की संप्रभुता की रक्षा और यूक्रेन का चार बार जिक्र करने के साथ ही रुस का जिक्र ना करके इशारों इशारों में ही बहुत कुछ कहने में सफल रहे हैं। इसी तरह से चीन को भी संदेश देने का प्रयास किया गया है। नया कोरिडोर बनाने और फ्यूल संकट को लेकर ग्लोबल वायोफ्यूल की वैश्विक समझ बनाना किसी सफलता से कमतर नहीं है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, डिजिटल इकोनोमी, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों के साथ ही युद्ध और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, महंगाई और आतंकवाद, कार्बन उत्सर्जन सहित चुनौतियों का मिलकर हल खोजने का सार्थक प्रयास माना जा सकता है। सउदी अरब के क्राउन प्रिंस का सम्मेलन में आना और एक दिन अधिक रुकना पाकिस्तान के लिए किसी तेज झटके से कम नहीं है।

इन सबसे इतर यह कि जी 20 सम्मेलन भारतीय कला, शिल्प, सभ्यता और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास से रुबरु कराने में भी सफल रहा है। भारत नाम को लेकर पक्ष विपक्ष मत हो सकते हैं पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने में यह सम्मेलन सफल रहा है। सबसे खास कि इस सम्मेलन में शाकाहारी भोजन परोसा गया तो दूसरी और मोटे अनाज को भी व्यंजनों में शामिल किया गया। सबसे खास और बड़ी बात यह कि भारत वन अर्थ, वन फैमेली, वन फ्यूचर की बात केवल कागजी नहीं कर उसे दुनिया के देशों के सामने प्रभावी तरीके से पूरी प्रतिवद्धता के साथ रखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा संदेश दिल्ली डिक्लरेशन सहित बिन्दुओं पर आमसहमति बनाने में सफलता प्राप्त कर भरोसे को कायम किया है। दुनिया के देश अब भारत की और आशाभरी नजरों से देखने लगे हैं। आने वाला समय भारत का होगा इसमें अब किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए।

हिन्द स्वराज्य

हिन्दुस्तान की दशा-2 (भाग-8)

गतांक से आगे...

प्रश्न- अंग्रेज दोनों कौमों का मेल होने देंगे?

उत्तर- यह सवाल डरपोक आदमी का है। यह सवाल हमारी हीनता को दिखाता है। अगर दो भाई चाहते हों कि उनका आपस में मेल बना रहे, तो कौन उनके बीच में आ सकता है? अगर तीसरा आदमी दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके, तो उन भाइयों को हम कच्चे दिल के कहेंगे। उसी तरह अगर हम — हिन्दू और मुसलमान-कच्चे दिल के होंगे, तो फिर अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक कंकड़ से नहीं तो दूसरे कंकड़ से फूटेगा ही। घड़े को बचाने का रास्ता यह नहीं है कि उसे कंकड़ से दूर रखा जाय, बल्कि यह है कि उसे पक्का बनाया जाय, जिससे कंकड़ का भय ही न रहे। उसी तरह हमें पक्के दिल के बनना है। हम दोनों में से कोई एक (भी) पक्के दिल के होंगे, तो तीसरे की कुछ नहीं चलेगी। यह काम हिन्दू आसानी से कर सकते हैं। उनकी संख्या बड़ी है, वे अपने को ज्यादा पढ़े-लिखे मानते हैं; इसलिए वे पक्का दिल रख सकते हैं। दोनों कौमों के बीच अविश्वास है, इसलिए मुसलमान लॉर्ड मोर्ले से कुछ हक माँगते हैं। इसमें हिन्दू क्यों विरोध करें? अगर हिन्दू विरोध न करें, तो अंग्रेज चौकेंगे, मुसलमान धीरे-धीरे हिन्दुओं का भरोसा करने लगेंगे और दोनों का भाईचारा बढ़ेगा। अपने झगड़े अंग्रेजों के पास ले जाने में हमें शरमाना चाहिए। ऐसा करने से हिन्दू कुछ खोने वाले नहीं हैं; इसका हिसाब आप खुद लगा सकेंगे। जिस आदमी ने दूसरे पर विश्वास किया, उसने आज तक कुछ खोया नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हिन्दू-मुसलमान कभी झगड़ेंगे ही नहीं। दो भाई साथ रहें तो उनके बीच तकरार होती है। कभी हमारे सिर भी फूटेंगे ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग एक-सी अकल के नहीं होते। दोनों जोश में आते हैं तब अकसर गलत काम कर बैठते हैं। उन्हें हमें सहन करना होगा। लेकिन ऐसी तकरार को भी बड़ी वकालत बघारकर हम अंग्रेजों की अदालत में न ले जायें। दो आदमी लड़ें, लड़ाई में दोनों के सिर या एक का सिर फूटे, तो उसमें तीसरा क्या न्याय करेगा? जो लड़ेंगे वे जख्मी भी होंगे बदन से बदन टकरायेगा तब कुछ निशानी तो रहेगी ही। उसमें न्याय क्या हो सकता है? दिखाता है।

क्रमशः ...

वसुंधरा और पायलट करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं?

निरंजन परिहार

वसुंधरा राजे और सचिन पायलट। दो अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां और अलग अलग ताकत। लेकिन राज्य एक और लक्ष्य भी एक - मुख्यमंत्री बनना। मगर दोनों दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों में दरकिनार। दोनों से पार्टी नेतृत्व नाखुश और दोनों की चुनाव में मुख्य भूमिका से बराबर की दूरी।

सचिन पायलट तो खैर बीते 5 साल से उनकी अपनी ही पार्टी में किसी गैर की तरह जी रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बारे में माना जा रहा था कि चुनाव आते आते वे फिर से मुख्यधारा में आ ही जाएंगी और अपने तेवर भी दिखाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव घोषित करने की तैयारी में है और पार्टियां भी तैयार हैं, लेकिन न तो कांग्रेस में पायलट की बाजी पलटती नजर आ रही और न ही बीजेपी में वसुंधरा को अपनी धरा पर किसी तरह की कोई खास भूमिका मिलने के आसार हैं। लग रहा है कि कांग्रेस की कमान तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ ही रहेगी और बीजेपी में अब चेहरे के नाम पर केवल नरेंद्र मोदी ही होंगे। वसुंधरा इसीलिए विकट संकट में हैं क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा, और पायलट इसीलिए पस्त हैं कि करें तो क्या करे!

वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों राजस्थान में अपनी अपनी पार्टियों में ताकतवर नेता हैं। दोनों एक दूसरे से कम नहीं। अल्पायु पायलट भले ही कम अनुभवी हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका जनाधार मजबूत, तो बीजेपी में वसुंधरा की बराबरी का अनुभवी कोई नहीं। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ साथ कुल 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, विपक्ष की नेता और जाने कितने पदों पर रही वसुंधरा राजे इन दिनों असाधारण रूप से केवल दर्शक की भूमिका में है।

कारण केवल यही है कि पार्टी आलाकमान अब उनको किसी भी तरह की बड़ी भूमिका देना नहीं चाहता। पार्टी की परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा राजे की उपस्थिति जरूर दिख रही है और कहीं राजनाथ सिंह, तो कही अमित शाह और कहीं नितिन गड़करी और जेपी नड्डा अपने भाषणों में वसुंधरा की सरकार में हुए कार्यों की प्रशंसा करके उन्हें खुश भी कर देते हैं। लेकिन कई प्रकार से सक्रियता व ताकत दिखाने के बावजूद वसुंधरा को बीजेपी ने अपनी चार में से एक परिवर्तन यात्रा का भी नेतृत्व नहीं सौंपा।

वजह यह कि बीजेपी अब राजस्थान में हर जगह नई उम्र का नया नेतृत्व उभारना चाहती है और उस नई पौध के साथ-साथ कई अन्य नेताओं को एक साथ बड़ा बनाना चाहती है। बीजेपी का मकसद यह है कि आने वाले 25-30 साल तक पार्टी में नई पीढ़ी आगे बढ़ती रहे व अपने दम पर सरकारें बनाती रहे। पुरानों को पालकर अब नयापन नहीं लाया जा सकता। इसलिए, राजनीति के कुछ अल्पज्ञानी भले ही यह मान रहे हों कि वसुंधरा राजे केंद्र को आंख दिखाती रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कम पसंद करते हैं, इसलिए वे उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते। मगर, इस तरह के बचकाने तर्क देने वाले वसुंधरा की आभा से अभिभूत लोग यह भूल जाते हैं कि दिल्ली में बैठे जो नेता इस चुनाव में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, वे राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं।

उधर, कांग्रेस में पायलट के पलटवार थम गए हैं। दो महीने से शांति है और इस शांति ने अब स्थापित शांति का रूप धर लिया है। कुछ दिन पहले तक पायलट के उद्देश्य आक्रामक थे और तेवर तीखे। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पार्टी में पायलट अपने पांव जमा ही नहीं पाए। अपनी ताकत दिखाने का आखिरी शक्तिशाली प्रयास किया अजमेर से जयपुर की पदयात्रा करके, मगर उनकी इस पदयात्रा से ज्यादा चर्चा रही उनके पांव के छालों की। वे मौन प्रदर्शन पर भी बैठे और नई दिल्ली में आलाकमान के सामने अपनी बात भी रख आए, जिसे राजनीतिक हलकों में अपना दुखड़ा रोने की संज्ञा मिलने से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ।

कांग्रेस आलाकमान के समक्ष पायलट ने जो तीन मांगें रखी, वे मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पल भर में ही जब स्वीकार कर ली गई तो उसी पल यह मान लिया गया था कि होना - जाना कुछ भी नहीं है। हुआ भी वहीं, पायलट की मांगों पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही विमर्श। पायलट फिर भी चुप हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे और किसी भी तरह की कोई राजनीतिक हलचल नहीं। बस, इतना जरूर है कि उन्हें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सदस्य ले लिया गया है, और राजनीतिक हलकों में इसे उनके मुंह पर चिप्पी चिपकाना कहा जा रहा है। बाद में तो खैर, राजस्थान कांग्रेस में चुनाव के लिए बनी 8 समितियों में किसी भी समिति में उनको न तो अध्यक्ष बनाया गया और न ही कोई प्रभावी जिम्मेदारी मिली।

खास बात यह भी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत के बाद कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद पायलट के जूनियरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मगर पायलट पार्टी में लगभग दरकिनार ही रखे गए हैं। हर साल 6 सितंबर को हजारों की भीड़ जमा करके जन्म दिन पर जोरदार जलसा करने वाले पायलट इस बार विधानसभा चुनाव के ऐन पहले भी, बिना कोई जलसा किए पहले ही विदेश चले गए। प्रियंका गांधी राजस्थान आई, तो वे मंच पर जरूर दिखे, लेकिन भूमिका कोई नहीं थी।

राजस्थान की राजनीति में, वसुंधरा और पायलट, दोनों सक्रियता दिखाने को बेताब हैं, मगर अपनी अपनी पार्टियों में कहीं भी कोई हलचल पैदा न कर पाने के कारण दोनों के समर्थक हैरान हैं। राजस्थान में निश्चित तौर पर वसुंधरा एक बहुत बड़े वर्ग की पहली पसंद हैं, खासकर महिलाओं में। उन्हीं की तरह प्रदेश के कई जिलों में पायलट को पसंद करने वालों की भी बड़ी संख्या है। लेकिन दोनों को उनकी पार्टी ही भाव नहीं दे रही। भले ही कुछ लोग कहें कि दोनों पार्टियों को इसके नुकसान भी उठाने होंगे, मगर सच यह है कि दोनों ही पार्टियों का आलाकमान अपने अपने इन दोनों नेताओं की ताकत को तौलने के बाद ही उनको दरकिनार किए हुए है।

पहले भी भारतीय सनातन संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर पाया

प्रह्लाद सबनानी

भारत आदि काल से ही एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास बताया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में विरासत पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और भारत में आर्थिक विकास के साथ ही सांस्कृतिक विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। जिसके चलते अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। बल्कि अब तो अन्य कई देश, विकसित देशों सहित, भी अपने आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के हल हेतु एवं अपने आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से भारतीय सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारत ने राजनैतिक स्वतंत्रता 75 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली थी, परंतु भारत की सनातन संस्कृति आदि काल से चली आ रही है एवं लाखों वर्ष पुरानी है। भारत को 'सोने की चिड़िया' के रूप में जाना जाता रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति का लोहा पूरे विश्व ने माना है। धर्म, दर्शन, विरासत, तीज, त्यौहार, जायका और अनेकता में एकता के दर्शन करने को पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती रही है। भारत को देव भूमि भी कहा गया है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है और यह समर्पण की भूमि है। हाल ही के समय में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संवारने और उसकी संवृद्धि के लिए विशेष रूप से पिछले दशक के दौरान अथक प्रयास किए गए हैं। हजारों वर्षों की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि कितने ही झंझावात क्यों न आए परंतु भारतीय सनातन संस्कृति अटूट रही। हालांकि कुछ देशों, जैसे ग्रीक, यूनान, ईरान आदि की तो सभ्यताएं ही समूल नष्ट हो गईं। भारतीय सनातन संस्कृति ने न केवल भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है बल्कि पूरे विश्व को ही भारत के साथ जोड़ा है। अब तो भारत में 'एक भारत- श्रेष्ठ भारत' के रूप में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा है। भारत ने जी-20 समूह के देशों की अपनी अध्यक्षता के दौरान कई अतुलनीय कार्य किए है। पिछले लगभग एक वर्ष के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सदस्य देशों की 200 से अधिक बैठकों का भारत के विभिन्न शहरों में आयोजन कर भारत ने पूरी दुनिया के समस्त देशों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत ने पूरी दुनिया को ही अपनी महान गौरवशाली सनातन संस्कृति, वैभवशाली विरासत, आध्यात्मिक क्षेत्र, आर्थिक विकास, आदि का परिचय देने में सफलता हासिल की है। भारत ने हाल ही के वर्षों में अपनी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल करने एवं अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने में जो सफलता पाई है वह मुख्य रूप से भारत की सनातन संस्कृति एवं परम्पराओं का पालन करते हुए ही प्राप्त की जा सकी है। इसके ठीक विपरीत विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद से विश्व के कई विकसित देश अभी तक कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूंजीवाद पर आधारित आर्थिक नीतियों के पालन से पश्चिमी देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। विकसित देशों में आज परिवार की प्रधानता एक तरह से समाप्त हो चुकी है। इस संदर्भ में यहां विशेष रूप से अमेरिका की स्थिति का उदाहरण दिया जा सकता है। अमेरिका में आज सामाजिक तानाबाना छिन्न-भिन्न हो चुका है। दंपतियों में तलाक की दर बहुत अधिक हो गई है जिसके चलते बच्चे केवल अपनी मां के पास रह जाते हैं एवं बड़ी संख्या में बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं है। अमेरिका में प्रत्येक 100 नागरिकों पर बंदूकों के 120 लाइसेंस जारी किए गए हैं, अर्थात कुछ नागरिकों के पास एक से अधिक बंदूक उपलब्ध है। बंदूक की सहज उपलब्धता के कारण आज अमेरिका में हिंसा की दर बहुत अधिक हो गई है। अमेरिका में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर पुलिस के 978 कर्मचारी तैनात है। इसके बावजूद, वर्ष 2020 में अमेरिका में मास शूटिंग (जिसमें 4 अथवा इससे अधिक नागरिकों की मृत्यु हो गई थी) की 610 घटनाएं हुईं। वर्ष 2021 में 690, वर्ष 2022 में 647 एवं इस वर्ष 9 मई 2023 तक 203 मास शूटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं।

जी20 सम्मेलन से नए दौर की शुरुआत

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 अध्यक्ष के नाते जब 'स्वस्ति अस्तु विश्व' यानी संपूर्ण विश्व सुखी हो के साथ शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा की तो ये कोरे शब्द नहीं थे। जी20 का नई दिल्ली शिखर सम्मेलन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और सफल माना जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बाद पहला सम्मेलन है जिसके घोषणा पत्र से कोई देश नाखुश या असंतुष्ट नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देश संतुष्ट हैं तथा रूस और चीन भी। इस कूटनीति को भारत ने कैसे साधा होगा इसकी कल्पना आसान नहीं है। 37 पृष्ठों के घोषणा पत्र में पृथ्वी, यहां के लोग, शांति व समृद्धि वाले खंड में चार बार यूक्रेन युद्ध की चर्चा है किंतु रूस का नाम कहीं नहीं है। सम्मेलन के पहले दिन दूसरे सत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करने की घंटी बजाई तभी साफ हो गया कि भारत की कूटनीति सफल रही है। सम्मेलन आरंभ होने के एक दिन पहले तक यूक्रेन से लेकर जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, विकासशील और कमजोर देश को वित्तीय सहायता व सस्ते कर्ज उपलब्ध कराने, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन रही थी। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध से जुड़ा पैराग्राफ खाली छोड़ना पड़ा था। भारतीय प्रयासों ने रंग लाया और घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता, आर्थिक चुनौतियां, हरित विकास, आतंकवाद, क्रिप्टो करेंसी, महिलाओं के उत्थान समेत वो सारे मुद्दे शामिल किए गए जिन्हें भारत ने तैयार किया था। इस एक पहलू से साफ हो जाता है कि अपनी अध्यक्षता में भारत ने किस तरह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, देशों के संबंध, राजनय, व्यक्ति के जीवन आदि से संबंधित भारतीय विचारों को लेकर पिछले एक वर्ष तक काम किया होगा। भारत के लगभग 60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकें जी20 की हुई हैं। इनमें कुल 112 परिणाम दस्तावेज व अध्यक्षीय दस्तावेज तैयार हुए। पिछले इंडोनेशिया की राजधानी बाली के सम्मेलन में कुल 50 परिणाम व अध्यक्षीय दस्तावेज स्वीकृत हुए थे। इनमें 73 परिणाम दस्तावेज यानी आउटकम डॉक्युमेंट हैं जो देश के विभिन्न शहरों में सदस्य देशों के मंत्रियों और अधिकारियों की ओर से बैठकों में बनी सहमति पर तैयार हुए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जिन पर बैठक नहीं हुई। जब भारत ने इसका नारा ही एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य दिया तथा इसके साथ वसुधैव कुटुंबकम जोड़ दिया तो फिर इसके परे कुछ हो ही नहीं सकता था। निश्चय ही इसके सदस्य देशों के साथ अन्य देशों को भी इन शब्दों के भारतीय अर्थ समझाए गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। भारत नाम को वैश्विक स्वीकृति की ठोस नींव पड़ चुकी है। भारत शब्द के साथ विश्व यह मानने को विवश होगा कि हम लाखों वर्ष पूर्व के प्राचीनतम राष्ट्र हैं। इस नाते भी जी20 सम्मेलन को इतिहास के अध्याय में याद किया जाएगा।

चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से सांसत में भाजपा

उमेश चतुर्वेदी

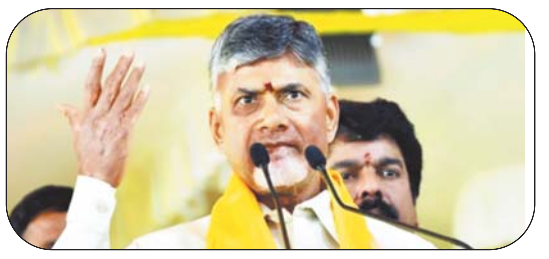

प्रतिष्ठा की लड़ाई बने दिल्ली सेवा विधेयक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रणनीतिक कौशल ही रहा कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े तेलुगू देशम और वाईएसआर कांग्रेस को ना सिर्फ संसद में साथ ला खड़ा किया, बल्कि विधेयक के लिए दोनों का समर्थन जुटा लिया। चूंकि आम चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा माना यह जा रहा था कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दलों के साथ मिलकर बीच की ऐसी राह निकाल लेगी, जिससे आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में लाया जा सके। लेकिन जिस तरह कौशल विकास घोटाले में वाईएसआर कांग्रेस की राज्य सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, उससे सबसे ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी लग रही है। दोनों दलों को साधना और सहयोग के बिंदु पर पहुंचा पाना अब बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होता नजर आ रहा है।

पिछले दो आम चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। लोकसभा में अपनी दमदार उपस्थिति के चलते वह अखिल भारतीय पार्टी होने का दावा कर सकती है, लेकिन यह कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक के इतर दक्षिण भारत के प्रदेश अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। पिछले दो चुनावों में थोड़ी सी उपस्थिति तेलंगाना में भी बन चुकी है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत नहीं की है, उसके मातृसंगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम इन राज्यों में भी चल रहे हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों से अपेक्षित समर्थन नहीं जुटा पाई है। चूंकि 2024 के आम चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा भाजपा चाहती है कि वह दक्षिण के राज्यों में भी अपनी पहुंच और पकड़ बनाए। अगर वह खुद नहीं बना सकती तो वह अपने सहयोगियों का कुनबा बढ़ाकर ऐसा करे। आंध्र प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक ताकतें, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और विपक्षी चंद्रबाबू नायडू को साथ लाने की कवायद भाजपा की उसी चाहत का नतीजा थी। स्थानीय राजनीति में चूंकि दोनों एक-दूसरे के विरोधी दल हैं, इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए साथ आना संभव नहीं है। ऐसा होने से दोनों के स्थानीय स्तर पर अस्तित्व का सवाल उठ खड़ा होगा। आंध्र प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव हों या लोकसभा चुनाव, भाजपा की यहां ऐसी उपस्थिति भी नहीं दिखी, जिसका उल्लेख किया जा सके। लेकिन 2019 के आम चुनाव में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को पचास फीसदी से कुछ ही कम यानी 49.89 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे, जबकि टीडीपी ने चालीस फीसदी से कुछ ही ज्यादा यानी 40.19 फीसद वोट हासिल किए थे। दोनों को प्राप्त मतों में साढ़े आठ फीसदी से ज्यादा अंतर था। इसका असर सीटों की संख्या पर भी दिखा। राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को 22 सीटों के साथ बंपर जीत मिली, जबकि टीडीपी को महज तीन सीटों से ही संतोष करना पड़ा।

लोकसभा के साथ ही यहां के विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें तो राज्य की जनता ने लोकसभा की तुलना में जगनमोहन रेड्डी को किंचित ज्यादा मत दिया, जिस कारण उसे 151 सीटों के साथ बहुत धमाकेदार जीत मिली। जबकि चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा में प्राप्त चालीस फीसदी से भी कम वोट मिला और उन्हें सिर्फ 23 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में अभी जिस तरह का माहौल है, उससे नहीं लगता कि यहां की राजनीतिक स्थिति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। हां, अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू जोर लगा रहे हैं। यहां यह भी याद कर लेना चाहिए कि कभी चंद्रबाबू नायडू की संयुक्त आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना समेत वाले राज्य में तूती बोलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए था, उसकी प्रमुख हस्ती नायडू भी थे। बाहर से समर्थन देने के बावजूद वाजपेयी सरकार से वे अपने राज्य के लिए हर प्रमुख मांग आसानी से मनवा लेते थे। एक दौर में चंद्रबाबू नायडू की आंध्र में राजनीतिक हैसियत ऐसी थी कि कोई भी नहीं सोच पाता था कि आंध्र प्रदेश से उनकी सत्ता जा सकती है। उनकी हालत कुछ कुछ आज के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जैसी थी। लेकिन जगनमोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी ने बतौर आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज्यव्यापी पदयात्राएं निकालीं और 2004 के विधानसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश छीन लिया। उसका असर लोकसभा के नतीजों पर भी दिखा और कांग्रेस व्यापक बढ़त हासिल करने में आगे रही। लेकिन बाद में वही कांग्रेस आंध्र से बाहर हो गई। तेलंगाना पर चंद्रशेखर राव का कब्जा है तो आंध्र पर कांग्रेस से अलग हो चुके राजशेखर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी का। ऐसे माहौल में भाजपा अगले आम चुनाव में अपनी किलेबंदी को चाकचौबंद करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसीलिए वह आंध्र प्रदेश के दोनों दलों को साध रही है। लेकिन कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद जगनमोहन रेड्डी ने बीजेपी के विकल्प सीमित कर दिए हैं। अब उसके सामने चुनौती है कि वह या तो चंद्रबाबू नायडू का साथ ले या फिर जगनमोहन रेड्डी के संग राजनीति का रथ आगे बढ़ाए। क्योंकि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के बाद एक तरह से दोनों दलों की दुश्मनी एक बार फिर सतह पर आ गई है, जो कुछ महीनों से नेपथ्य में जाती दिख रही थी। शायद इसके पीछे बीजेपी का भी योगदान था। वैसे चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय स्तर पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें तेलुगू देशम का साथ स्थानीय भाजपा भी दे रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मजबूरी है कि वह एनडीए के पुराने साथी के साथ खड़ी नजर आये तो वहीं सत्ताधारी जगनमोहन के विरोध में भी दिखे। जबकि गठबंधन राजनीति में चंद्रबाबू और जगनमोहन दोनों ही अपने अपने कारणों से धुर कांग्रेस विरोधी हैं। दोनों ही चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एलायंस हो तो वो बीजेपी के साथ ही रहे। चंद्रबाबू नायडू के पास दिल्ली में तीसरे मोर्चे का विकल्प रहता था लेकिन जब से केन्द्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावना खत्म हुई है वो अब कोई नया विकल्प नहीं तलाश सकते। कुछ ऐसा ही हाल जगनमोहन का है जो कांग्रेस द्वारा दी गयी निजी पीड़ा को आज तक नहीं भूले हैं। उनके लिए भी सुविधाजनक यही रहेगा कि वह केन्द्रीय स्तर पर बीजेपी के साथ ही खड़े दिखाई दें।

चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की लाईन फिर खिंच गई

अजय सेतिया

भारतीय जनता पार्टी की किस्मत अच्छी है कि उसके विरोधी उसे कोई न कोई ऐसा मुद्दा दे देते हैं, जिससे उसकी खिसकती जमीन फिर से उसके कब्जे में आ जाती है। मोदी और भाजपा विरोध में बना इंडी एलायंस सेक्यूलरिज्म के नाम पर हिन्दू और सनातन धर्म विरोध पर आकर अटक गया है। इंडी एलायंस के पावरफुल घटक डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी के बयान से इंडी एलायंस में खलबली मच गई है। उनका बयान सिर्फ सनातन धर्म विरोधी नहीं है। बल्कि इस बात का खुलासा है कि इंडी एलायंस का गठन ही सनातन धर्म विरोध के आधार पर किया गया है। अब इंडी एलायंस के सभी घटक दलों को सफाई देनी पड़ेगी कि सनातन धर्म पर उनके क्या विचार हैं।

एक तरफ यह राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया है, तो दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद ने 30 अक्टूबर से देश भर में यात्राओं का आयोजन करने का एलान कर दिया है। यह वह समय होगा, जब पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो रहे होंगे। स्टालिन के बयानों और विश्व हिन्दू परिषद की यात्राओं के एलान से हिन्दू-गैर हिन्दू की लड़ाई का नया मैदान तैयार हो गया है, जिसका राजनीतिक फायदा भाजपा को ही होगा। बिलकुल वैसे ही जैसे रामरथ यात्रा ने देश में हिन्दू नवजागरण का माहौल बनाया था। यात्राओं का मकसद सत्य सनातन हिन्दू धर्म पर हो रहे हमलों का विरोध करना है। खुद को हिन्दू नेता कहने वाले और बाबरी ढाँचे को तोड़ने का श्रेय लेने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का यह बयान भी चौंकाने वाला है कि श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर के शिला न्यास के बाद गोधरा जैसा कांड हो सकता है। सन 2002 में रामजन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करके लौट रहे हिन्दू तीर्थ यात्रियों को गोधरा में उनके ट्रेन के डिब्बे को आग लगा कर ज़िंदा जला दिया गया था। जिसके बाद गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, इन्हीं दंगों के कारण सोनिया गांधी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था।

2004 में केंद्र में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू करवा दी थी। कांग्रेस सरकार के इशारे पर सीबीआई ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को सीबीआई के दफ्तर में बुला कर कई घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता चला गया। उनका कद इतना बढ़ा कि भाजपा को मजबूर होकर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा था।

स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटों के सनातन धर्म विरोधी बयानों और उसमें उद्धव ठाकरे का बयान जुड़ने के बाद तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि इंडी एलायंस की रणनीति हिन्दुओं को जातियों में बांटना और अल्पसंख्यकों को अपने साथ लाकर भाजपा और मोदी को हराने की है। क्योंकि जब से उदयनिधि का बयान आया है, तबसे गठबंधन के सभी दलों का

सेक्यूलरिज्म खुल कर सामने आ गया है। उनका बयान सनातन धर्म का समूल नाश करने का था। इंडी गठबंधन के किसी नेता ने अभी तक उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा नहीं की थी, और अब यह नया बयान इंडी गठबंधन पर ही आ गया। अब तक तो इंडी गठबंधन के नेता यही कह रहे थे कि सबको बोलने की आज़ादी है।

लेकिन जब नूपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर एक डिबेट के दौरान बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए एक एतिहासिक तथ्य सबके सामने रखा था, तो इन्हीं सब लोगों ने नूपुर शर्मा की निंदा की थी। जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को न सिर्फ प्रवक्ता पद से हटा दिया था, बल्कि उन्हें भाजपा से भी निलंबित कर दिया था। अब बिलकुल वैसी ही हिन्दू धर्म विरोधी टिप्पणी इंडी एलायंस के एक नेता की आई है, तो उन्हें निलंबित करना तो दूर की बात, उनकी निंदा भी नहीं की जा रही। इंडी गठबंधन के लगभग सभी नेताओं ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का बयान देकर मामले को रफादफा करने की कोशिश की है।

कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अभिव्यक्ति की आज़ादी बता कर उदयनिधि स्टालिन का बचाव किया था। उनकी निंदा करने की बजाए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। कांग्रेस की तरफ से सर्व धर्म समभाव की बात कह कर कांग्रेस का पिंड छुडाने की बात कही, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि गठबंधन सनातन धर्म के विरोध के आधार पर बना है, उसका आधिकारिक जवाब गठबंधन की ओर से नहीं दिया जा रहा।

इसलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 सितंबर को एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए इंडी गठबंधन से पूछा है कि वह डीएमके नेताओं के बयान पर अपनी स्थिति साफ़ करे। क्या यह सच है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म के विरोध में खड़ा किया गया है। वैसे सनातन विरोधी गठबंधन के पीछे उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रणनीति बताया। बोलने की आज़ादी को ढाल बना कर स्टालिन का बचाव करने वालों से नड्डा ने पूछा है कि क्या संविधान किसी धर्म की आलोचना का अधिकार देता है। नड्डा ने कहा कि प्रियंक खड़गे का सनातन विरोधी बयान ही कांग्रेस की आधिकारिक लाईन है।

नड्डा को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौक़ा इसलिए मिल गया, क्योंकि इसी मुद्दे पर राहुल गांधी का फ़्रांस से बहुत ही दिलचस्प बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत सब पढ़ रखे हैं। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद के नेता ही उनकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर खिल्ली उड़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने रामायण पढ़ी होती, तो उनकी सरकार सुप्रीमकोर्ट में हल्फिया बयान देकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाती। रामसेतु को तोड़ने की वकालत नहीं करती।

अगर राहुल गांधी को हिंदुइज्म का जरा भी ज्ञान होता, तो उन्हें उदयनिधि के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर तकलीफ होती और वह इतने दिनों तक अपनी जुबान बंद नहीं रख पाते। स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे की सनातन विरोधी टिप्पणी ने भाजपा को इंडी गठबंधन के खिलाफ हथियार दे दिया है। इंडी गठबंधन के दो अन्य दलों से जुड़े बिहार के शिक्षामंत्री चन्द्रशेखर और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम पहले ही हिन्दू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। अब इंडी एलायंस के नेताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का दवाब झेलना पड़ेगा।

शादी से पहले दुल्हन को करने चाहिए ये काम, हर कोई होगा इंप्रेस

शादी हर लड़की के जीवन का बहुत खास मौका होता है। कहते हैं कि शादी के बाद जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। महिला शादी के बाद एक नए परिवार की सदस्य बन जाती है। अनजान लोगों से रिश्ता जुड़ने के बाद उसके लिए परिवार में शामिल होना और नए रिश्ते को मजबूत बनाना बड़ी चुनौती होती है।

ऐसे में शादी से पहले ही लड़कियों को कुछ काम कर लेने चाहिए, ताकि शादी के दौरान हर कोई उन से इंप्रेस हो जाएं। पति और ससुराल वालों से दुल्हन का अच्छा और मजबूत रिश्ता बन सके, इसके लिए शादी से एक महीने पहले कुछ कामों को जरूर करें। अगर आपकी शादी भी करीब है तो जल्द से जल्द यहां बताएं हुए कामों को निपटा लें ताकि हर कोई आपसे खुश हो जाए और ससुराल में खुले दिल से आपका स्वागत किया जाए।

स्किन केयर

शादी से पहले सबसे जरूरी है एक दुल्हन के लिए अपने लुक्स पर काम करना। 'ब्यूटी इज द फर्स्ट इम्प्रेशन' यानी किसी भी व्यक्ति में सबसे पहले सामने वाले लोग उनके लुक को ही देखते हैं। शादी के मौके पर बहुत सारे रिश्तेदार, मेहमान शामिल होते हैं। ऐसे में सुंदर दिखना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि ससुरालवालों के सामने आप एक अच्छी छाप छोड़ सकें। शादी होने वाली है तो त्वचा का ख्याल रखना शुरू कर दें। कुछ घरेलू स्किन केयर टिप्स भी अपना सकते हैं।

शादी की खरीदारी

शादी समारोह एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें हर किसी की नजर दुल्हन पर होती है। शादी में काम भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए दुल्हन को अपने सारे काम शादी से एक महीने पहले ही निपटा लेने चाहिए। शादी के जोड़े से लेकर अन्य सभी जरूरी सामान की खरीदारी पहले से कर लें ताकि तारीख नजदीक आते ही हड़बड़ाहट में कोई गलती न हो जाए और आपका खास दिन खराब हो जाए।

अधूरे काम पूरे करना

अगर आप नौकरी करती हैं या आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं तो शादी से पहले उन्हें पूरा कर लें। अधूरे कामों को निपटा लें ताकि शादी के वक्त दुल्हन फ्री होकर रस्मों को ठीक से निभा सकें। ऐसा न हो कि शादी के समय आपके ऊपर काम का बोझ आ जाए या शादी के तुरंत बाद आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने में जुट जाएं। इससे आप न तो अपनी शादी को एन्जॉय कर पाएंगी और ससुराल वालों को वक्त न देने पर वह भी नाखुश हो सकते हैं।

ससुराल वालों को जानना

हर दुल्हन को शादी से पहले अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। जैसे परिवार में कौन-कौन है?

घर के बच्चों के क्या नाम हैं? ऐसी ही कुछ अन्य बातें। ताकि शादी के बाद अनजाने में आपसे कोई गलती न हो जाए और ससुराल वालों के सामने आप का इंप्रेशन खराब हो जाए।

बिस्तर पर लेटकर करें ये योगासन सेहत को होंगे फायदे

गलत लाइफस्टाइल और खानपान से लोगों की सेहत पर प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण लोग कई बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। इन में मोटापा, थकान, शरीर दर्द और तनाव आदि शारीरिक और मानसिक समस्या शामिल हैं। इस तरह की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए योगासन लाभकारी होता है। योगासन का नियमित अभ्यास गलत जीवन शैली और पौष्टिक आहार की कमी से होने वाली समस्याओं से राहत दिलाता है। हालांकि भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोगों के पास योग या व्यायाम करने तक का समय नहीं मिल पाता। लेकिन सेहत को दुरुस्त रखने के लिए कुछ ऐसे योगासन हैं जो रोज सुबह नींद खुलने के बाद आप बेड पर ही कर सकते हैं। सुबह सुबह योगासन का अभ्यास मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। योगासन से शारीरिक समस्याएं कम होने के साथ ही तनाव और चिंता भी कम होती है। जानिए उन पांच योगासनों के बारे में, जिन्हें रोजाना सुबह आसानी से आप बिस्तर पर कर सकते हैं।

भुजंगासन

रोजाना भुजंगासन का अभ्यास करने से भुजाएं मजबूत होती हैं। मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे बेली फैट कम होता है और रीढ़ में लचीलापन आता है। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए बिस्तर पर पेट के बल सीधा लेटकर दोनों हाथों को कंधे के सामने ले आएं। फिर दोनों हाथों को कंधे पर सामने लाते हुए पूरा शरीर एक सीध में रखें। अब ऊपरी हिस्से को भुजाओं से उठाएं और पैर सीधे रखते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा हवा में रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं।

बटरफ्लाई पोज

बद्धकोणासन को बटरफ्लाई पोज कहते हैं, जिसके अभ्यास से हिप्स और जांघों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और चर्बी कम होती है। पैरों में मजबूती और हिप्स शेप के लिए भी यह योगासन फायदेमंद है। इस योगासन को करने के लिए बिस्तर पर सीधा बैठकर दोनों पैरों के घुटनों को अंदर की तरह मोड़ें। अब पैरों के दोनों तलवे आपस में जोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें। अब जांघों को हिलाएं। इसी अवस्था में रहने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं।

पवनमुक्तासन

शरीर में लचीलेपन और रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए पवनमुक्तासन करें। पवनमुक्तासन से शरीर की थकान दूर होती है। इस आसन को करने के लिए बिस्तर पर लेटकर दोनों पैरों को आपस में मोड़ लें। फिर घुटनों को छाती पर लगाने हुए दोनों हाथों से पैरों को समेटें। इसी अवस्था में रहते हुए लंबी-लंबी सांस लें और छोड़ें।

विपरीत करणी

इस आसन को करने से ब्लड सर्कुलेशन सीधा मस्तिष्क तक पहुंचता है और दिमाग तेजी से चलता है। मस्तिष्क तनाव मुक्त होता है और डार्क सर्कल सही होकर त्वचा ग्लो करती है। विपरीत करणी योगासन करने के लिए बिस्तर पर लेटकर पैरों को दीवार से सटाएं। फिर पैर को सीधा रखते हुए शरीर को भी सीधा कर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें फिर सामान्य हो जाएं।

अर्ध मत्स्येन्द्रासन

अर्ध मत्स्येन्द्रासन के अभ्यास से हिप्स और जांघ की मांसपेशियों का फैट कम होता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने के साथ ही कमर की चर्बी कम होती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन को करने के लिए बिस्तर पर पहले दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब शरीर को सीधा रखते हुए बाएं पैर के घुटनों से मोड़कर दाएं पैर को उठाकर बाएं घुटने पर ले लाएं। अब दाएं हाथ की कोहनी को दाएं पैर के घुटने के ऊपर रखें। इसी अवस्था में रहने के बाद दूसरी तरफ से यह आसन दोहराएं।

बच्चों को पढ़ाना है संस्कृति का पाठ तो अपनाएं ये टिप्स, त्योहारों पर कराएं ये काम

बच्चों को अपनी सांस्कृतिक विरासत और उत्सवों के बारे में जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है इसलिए जरूरी है कि आप उन्हें अनुष्ठानों और समारोहों से परिचित कराएं। त्योहार लोगों को

एक साथ लाते हैं और समाज में अपनेपन की भावना पैदा करते हैं। खासकर बच्चे तो बड़ों से ज्यादा त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं लेकिन आजकल बच्चों की उत्सुकता और ऊर्जा सिर्फ टेक्नोलॉजी में जाया हो रही है।

ऐसे में जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों को उत्सवों से जोड़ें और उनके महत्व बताएं, ताकि अपनी परंपराओं के प्रति उनकी खुशी एवं उत्साह बरकरार रहे। चूंकि बच्चे हर चीज के बारे में जिज्ञासु होते हैं, लिहाजा त्योहारों और उनमें छिपी परंपराओं के बारे में जानना उन्हें रोमांचक भी लगेगा। इसके लिए कुछ आसान तरीके भी हैं।

साफ-सफाई में भागीदारी

जब भी कोई अनुष्ठान, पर्व या उत्सव आता है तो आप घर की साफ-सफाई और सजावट में जुट जाती हैं। इस काम में बच्चों को भी शामिल करें, जिससे उनके मन में भी उत्सवों, अनुष्ठानों के आने की खुशी बनी रहे। बच्चों से छोटे-मोटे काम करने को कहें। आप उनसे कूड़ा-कचरा उठाकर कूड़ेदान में डालने, फर्नीचर की झाड़-पोंछ करने जैसे काम करा सकती हैं। इससे उनमें काम करने की आदत भी पडेग़ी।

पकवान बनाने में सहयोग

त्योहार आने पर सभी घरों में पकवान बनाए जाते हैं। आप इस काम में भी बच्चों की मदद ले सकती हैं और छोटे-छोटे काम कराकर उन्हें जिम्मेदारी का अहसास करा सकती हैं कि त्योहारों पर उन्हें भी काम करना है। इससे उनमें बचपन से ही साथ में काम करने की भावना पैदा होगी। बच्चे साथ में पकवान बनाएंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी और वे त्योहार का दुगुना मजा उठाएंगे।

रचनात्मकता जरूरी

बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दें। त्योहार या समारोह के दौरान उन्हें पारंपरिक पोशाक पहना कर, सजावट और पकवान बनाने में मदद लेकर और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी परंपराओं की जानकारी दें, जिससे वे बचपन से ही अपनी संस्कृति को जान सकें और उत्सवों का मजा ले सकें।

कहानियां और फिल्में

हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, जो हमें सकारात्मक संदेश देती है। इसलिए समय-समय पर आप बच्चों को अपने त्योहारों और परंपराओं की जानकारी किताबों द्वारा या फिल्में दिखाकर भी दे सकती हैं। जब आप बच्चे को कुछ रीति-रिवाजों के बारे में समझाती हैं तो वे उसे उबाऊ और बोर लगते हैं। वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता इसलिए त्योहारों के बारे में कहानी सुनाकर, पढ़कर या फिर उस विषय पर बनी कोई फिल्म दिखाकर आप जानकारी को उसके लिए रुचिकर बना सकती हैं, ताकि वह उत्साहित होकर अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करे।

मेल-मिलाप की भावना

अगर आप अपने बच्चों को त्योहारों से जोड़ेंगी तो उनमें मेल-मिलाप की भावना बढेग़ी। आज बच्चे भी अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे में मिल-जुल कर त्योहार मनाने से उनका अकेलापन दूर होगा। अपने बच्चे को त्योहारों पर रिश्तेदारों, परिचितों और पड़ोसियों के घर जरूर लेकर जाएं, ताकि वह सबसे घुले-मिले और त्योहारों को मिल-जुल कर मनाना सीखे।

हमेशा प्रोत्साहन

आजकल स्कूलों में भी बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में आप बच्चों को उनमें बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उनमें उत्साह पैदा हो। आप बच्चे को त्योहार से जुड़ी कविता या भाषण भी तैयार करा सकती हैं। जब बच्चा मंच पर त्योहार से संबंधित कविता या भाषण बोलेगा तो उसे अच्छा भी लगेगा और साथ में अपने उत्सवों के बारे में जानकारी भी हासिल हो जाएगी।

चश्मा लगाने से चेहरे पर पड़ गए हैं निशान तो करें इन चीजों का इस्तेमाल, मिलेगी दमकती त्वचा

एक समय था, जब एक उम्र के बाद ही आंखों पर चश्मा लगता था। उसकी वजह थी, अच्छा खानपान और व्यवस्थित लाइफस्टाइल लेकिन आज समय बदल गया है। आज के वक्त में

बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और बाहर के उल्टे-सीधे खाने की वजह से लोगों की आंखों पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार मोबाइल चलाने की वजह से आंखों दृष्टि और ज्यादा कमजोर होती जा रही है।

मोबाइल से निकलने वाली किरणों की वजह से कम उम्र में ही बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, जिसके चलते छोटी उम्र में ही बच्चे चश्मा लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब चश्मा लगातार लगाना पड़ता है तो उससे चेहरे पर निशान पड़ने लगते हैं। एक समय के बाद ये निशान काफी भद्दे लगने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको इन निशानों को मिटाने के कुछ घरेलू तरीके बताने जा रहे हैं ताकि आप भी घर बैठे चेहरे के इन निशानों से छुटकारा पा सके।

आलू

चश्मे से होने वाले इन निशानों को हटाने के लिए आपको बस कच्चे आलू की जरूरत होगी। इसके इस्तेमाल के लिए एक कच्चे आलू को पीस कर रस निकाल लें। इस रस को कॉटन बॉल से निशान वाली जगह पर अप्लाई करें। कुछ ही दिनों में आपको फायदा जरूर मिलेगा।

खीरा

चश्मे का निशान हटाने के लिए खीरे का रस काफी फायदेमंद होता है। आपको बस खीरे का रस निकाल कर उंगली से इसे निशान पर लगाना है।

गुलाब जल

स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में गुलाब जल काफी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे पर चश्मे से हुए निशान को हटा सकती हैं। इसके लिए आपको बस रोज सोने से पहले कॉटन बॉल को गुलाब जल में भिगो कर आधे घंटे के लिए चेहरे के निशान पर रखना है।

संतरे का छिलका

संतरे के छिलके के पेस्ट में कुछ बूंदे गुलाब जल की मिलाकर आप इसे निशान पर अप्लाई करें। कुछ ही दिन में आपको फायदा दिखने लगेगा।

टमाटर का रस

चेहरे पर ग्लो लाने के लिए टमाटर का रस काफी फायदा करता है। आप इसकी मदद से चेहरे पर पड़े निशान को भी हटा सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आपको बस टमाटर का जूस निशान वाली जगह पर अप्लाई करके आधा घंटे के लिए छोड़ना है।

एलोवेरा

अगर आपके चेहरे पर कई तरह की परेशानियां हैं तो रोजाना रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल को कॉटन बॉल में लेकर इसे निशान वाली जगह पर अप्लाई करें। कुछ ही दिन में चेहरे के निशान गायब हो जाएंगे।

मेलजोल से होता है बच्चों का विकास जानिए कैसे सिखाएं घुलना-मिलना

कई बच्चे स्वभाव से शर्मीले होते हैं और बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं। कई बच्चे मोबाइल, लैपटॉप को ही अपनी दुनिया समझते हैं और पड़ोसी का नाम भी नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वे मोबाइल के जरिये पूरी दुनिया के साथ सोशल हैं। माता-पिता के लिए यह एक चुनौती होती है, जब बच्चे दोस्त नहीं बना पाते या उन्हें सोशल होने में कठिनाई आती है। पढ़ाई, खेल-कूद के साथ बच्चों को सोशल वैल्यू देना भी जरूरी है। अगर वे चुपचाप और अकेले रहते हैं तो उनका विकास रुक जाता है। मेल-जोल से उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, हिम्मत खुलती है और नई चीजें जानने का मौका मिलता है। इसलिए बच्चों को यह समझना जरूरी है कि मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है, जो जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मसम्मान के लिए सामाजिक संबंध जरूरी हैं, लेकिन नए लोगों से घुलना-मिलना और बातचीत करना बच्चे के लिए काफी कठिन होता है। ऐसे में आप क्या करती हैं?

आस-पास क्या चल रहा है

कई बच्चे पहले से ही सोशल होते हैं। उन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है। कई बच्चे घर में रिश्तेदार आते ही कमरे में चले जाते हैं। ऐसे में माता-पिता उनको सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें, जैसे कि उन्हें पानी का ग्लास लाने को कहें या बड़ों का अभिवादन करना सिखाएं, ताकि उन्हें पता रहे कि आस-पास क्या चल रहा है। सामाजिक होने से बच्चे खुद को खुलकर अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिससे आस-पास के लोग भी उनसे हमेशा खुश रहते हैं।

नए लोगों से बातचीत

कई बच्चे माता-पिता या नजदीकी लोगों के अलावा किसी अन्य से

ज्यादा खुलते नहीं हैं। ऐसे में वे अंतर्मुखी रह जाते हैं और बाहरी दुनिया से उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। आज के समय में बच्चों को एक्टिव और इंटरेक्ट होना बेहद जरूरी है। इसलिए माता-पिता, बच्चों को बात करना सिखाएं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अकेलापन दूर होगा। बच्चों को दूसरे लोगों के साथ खुलने के लिए दोस्त बनाना सिखाएं। इसके लिए उन्हें सांस्कृतिक, एथलेटिक, धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने को प्रेरित करें।

शेयरिंग-केयरिंग

बच्चों का मन कोरा होता है और सरल भी, मगर कई बच्चों का स्वभाव शेयरिंग-केयरिंग का नहीं होता। ऐसे में माता-पिता उन्हें दोस्तों के बीच शेयरिंग- केयरिंग करना सिखाएं। बुरे वक़्त में दोस्तों की मदद करने से बच्चों में सहयोग, सद्भावना की भावना पनपेगी। बच्चों को दोस्ती की प्रेरक कहानियां सुनाएं।

सवाल करना

कई बच्चे जो सुनते हैं, चुपचाप उसे अंदर समा लेते हैं। लेकिन अगर वे सवाल नहीं करेंगे तो उनका विकास रुक जाएगा। इसलिए माता-पिता, बच्चों को सवाल करना सिखाएं। इससे उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे नई चीजें जान पाएंगे, किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे।

ताकत को पहचानें

हर बच्चे के अंदर एक खास गुण होता है। वही उसकी ताकत है। इसलिए बच्चों से जबरदस्ती कुछ भी न कराएं। उनकी प्रतिभा को समझकर, बच्चे की ताकत क्या है, उसे जानकर ही आगे बढ़ें। माता-पिता बच्चे के गुणों को पहचानें।

बच्चों के लिए रोल मॉडल

पहले खुद सोशल बनें। माता-पिता काम के अलावा भी वक्त निकालें, बच्चों के साथ बैठें और सोशल हों, ताकि बच्चे उन्हें देखकर ये सारे गुण सीख सकें।

बच्चों के सोशल न बन पाने के पीछे माता-पिता भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, जितने कि बच्चे, क्योंकि एकल परिवार में पेरेंट्स के पास ही बच्चों के लिए वक्त नहीं है, वे खुद बच्चों के साथ सोशल नहीं हैं।

दूसरी ओर, मोबाइल ने बच्चों को वर्चुअली तो सोशल बना दिया, लेकिन अपनों से दूर कर दिया। माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे हफ्ते में एक दिन बच्चों के लिए निकालें, उन्हें बाहर की दुनिया से रूबरू कराएं। इससे उनके अंदर रिश्तों की समझ बढ़ेगी और वे सोशल बनेंगे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री आज करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान, वह दोनों चुनावी राज्यों में 57 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि मध्य प्रदेश में मोदी जहां बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर सहित 50,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं और राज्यभर में 10 नयी औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ में वह रेल क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर, नर्मदापुरम में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र और रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे।

देश का नेतृत्व करने के लिए नीतीश तैयार : ललन सिंह

पटना। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने नालंदा के हरनौत प्रखंड की एक रैली का अपना वीडियो भाषण सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के रूप में कार्य करने और बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार पर एक भी आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पांच बार सांसद रहे और केंद्रीय रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद या इंडिया गुट के भीतर किसी भी पद की आकांक्षा नहीं करने के बार-बार दिए गए दावे को उनकी जद (यू) ने मंगलवार को खारिज कर दिया, जब पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने गढ़ नालंदा में एक बड़ी सभा में घोषणा की- आपका नेता अब देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जद (यू) ने बाहरी तौर पर अनिच्छुक नीतीश को इंडिया गठबंधन के संभावित प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया है।

पवार के घर हिंदू धर्म को खत्म करने 26 दलों की बैठकः भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुंबई में बुधवार को शरद पवार के घर एनसीपी यानी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इसमें हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त किया जाए उसे लेकर 26 दल बैठक करेंगे। पात्रा ने कहा, कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि आज इनके बीच सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। मगर सुबह से ये भी देख रहे हैं कि इनके बीच सुबह से ही खींचातानी चल रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई सीटों के बंटवारे, प्रचार-प्रसार, मुद्दों और घोषणापत्र से जुड़ी बैठक नहीं है। जैसे 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 राजनीतिक दलों का एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है और किस प्रकार हिंदू धर्म को समाप्त करना है। आज उसी विषय को लेकर इनकी बैठक होने वाली है। भाजपा नेता ने कहा, अगर किसी और धर्म के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया होता, तो आज पूरे विश्व मे हाहाकार मच गया होता।

आजम खां के ठिकानों पर आईटी ने की छापेमारी

लखनऊ। पूर्व मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार सुबह छापा मारा। आयकर विभाग की टीम द्वारा रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में सुबह से आजम खां के जौहर ट्रस्ट में अंजाम दी गई गड़बड़ियों के सुराग तलाशे जा रहे हैं। सीतापुर में आजम के करीबी रीजेंसी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। दो गाड़ियों से आए आयकर विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। रामपुर में सपा विधायक नसीर खां के घर पर आयकर की छापेमारी की गई। आजम के हमसफर रिसॉर्ट पर भी आयकर विभाग के अफसरों ने छापेमारी की है। इसी तरह मध्य प्रदेश के विदिशा में भी आयकर विभाग की टीम ने बड़ा बाजार क्षेत्र में रहने वाले समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के निवास पर छापेमारी की।

अमित शाह 16 को बिहार के दो जिलों का करेंगे दौरा

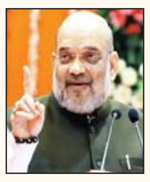

नईदिल्ली। भारत के गृह मंत्री अमित शाह फिर एकबार बिहार आने वाले हैं। आगामी 16 सितंबर को गृह मंत्री झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र आएंगे। झंझारपुर से अमित शाह विपक्षी दलों पर निशाना साधेंगे। वहीं पहली बार अमित शाह अररिया जिले का भी दौरा करने वाले हैं। 16 सितंबर को ही गृह मंत्री जोगबनी भी जाएंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर दोनों जगहों में तैयारियां तेज कर दी गयी है। भाजपा नेताओं ने कैंप करना शुरू कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आगामी 16 सितंबर यानी शनिवार को मधुबनी के झंझारपुर पहुंचेंगे। जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसी दिन गृह मंत्री अररिया जिले का भी दौरा करेंगे। अमित शाह पहली बार अररिया आ रहे हैं। जिसे लेकर भाजपा ने तैयारी भी तेज कर दी है। आगामी 16 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह के सीमावर्ती क्षेत्र जोगबनी के संभावित दौरे को लेकर अधिकारियों की हलचल बढ़ गई है।

मंत्रिमंडल ने जी20 के सफल आयोजन पर पीएम को बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हाल ही में सम्पन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और भारत के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों की ओर से उन्हें (प्रधानमंत्री को) बधाई दी गई। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि जी20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है और इसके सफल आयोजन की चर्चा न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में हो रही है।

दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत का परिचायक

अनुराग ठाकुर के अनुसार, इसमें कहा गया है कि नयी दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया में एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने हमेशा समावेशी विकास और समावेशिता की बात की है और जी20 समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल किया जाना, इसे सिद्ध करता है।

सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि भारत आज वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनकर उभरा है। 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। ठाकुर ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उज्ज्वला स्कीम के तहत 75 लाख मुफ्त कनेक्शन को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने त्योहार से पहले आमलोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला स्कीम के लिए 75 लाख नये एलपीजी कनेक्शन को मंजूरी दे दी गयी है। केंद्र सरकार ने स्कीम के तहत 1,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। इससे पहले 30 अगस्त को सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये तक घटा दिए थे। जिसके बाद से उज्जवला योजना के तहत ग्राहकों को 400 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता मिलने लगा था। इसके साथ ही, सरकार ने 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इसी के तहत आज 1,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी है। योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त देने का एलान किया है। रक्षा बंधन से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार के इस ऐलान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये फैसला रक्षा बंधन पर आम महिलाओं को तोहफे के तौर पर दिया गया है।

केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक योजना के तहत 1650 करोड़ रुपये खर्च ओएमसी कंपनियों को दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत, कंपनी को प्रति कनेक्शन 2200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पहला रिफिल यानी खाली सिलेंडर भरवाना और मुफ्त चूल्हे का जिसका खर्च ओएमसीएस का खर्च केंद्र सरकार के खाते से होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद बताया था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपये में मिलेगा। ठाकुर ने कहा कि इस पहल का मकसद परिवारों को राहत उपलब्ध कराना है। इसके साथ सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में कटौती से महिलाओं की सहूलियत बढ़ेगी तथा उनका जीवन और भी आसान होगा।

लोगों पर वित्तीय बोझ होगा कम

केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि ये निर्णय लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करने और उनकी बेहतरी के लिये सरकार की तरफ से जारी प्रयासों का हिस्सा है। रसोई गैस के दाम में कमी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने और उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को आज मंजूरी मिली है। इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुवेन फार्मास्युटिकल्स लि. में 9,589 करोड़ रुपये तक विदेशी निवेश की अनुमति दी। ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तीसरे चरण का मकसद ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। कागज रहित अदालतों के लिए ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा संग्रहीत करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

विशेष सत्र के चार दिन शेष एजेंडे का पता नहीं : कांग्रेस

संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित

नईदिल्ली। कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के लिए एजेंडे की सूचना नहीं होने को लेकर बुधवार को एक बार फिर सवाल उठाया और कहा कि सत्र आरंभ होने में केवल चार दिन शेष है, लेकिन शायद 'एक व्यक्ति' को छोड़कर एजेंडे के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अतीत में हुई संसद की कुछ विशेष बैठकों का उल्लेख भी किया और कहा कि विशेष बैठकों से पहले कार्यसूची की जानकारी उपलब्ध होती थी।

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज 13 सितंबर है। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र चार दिन बाद शुरू होगा और एक व्यक्ति (शायद दूसरे को भी) को छोड़कर किसी को भी एजेंडे की जानकारी नहीं है। पिछले प्रत्येक अवसर पर जब भी विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थीं, तो कार्यसूची के बारे में पहले से जानकारी होती थी।'' संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

जयराम रमेश ने कहा, ''26 नवंबर, 2019 को संविधान की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय कक्ष में विशेष बैठक हुई। 30 जून, 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को केंद्रीय कक्ष में संयुक्त विशेष सत्र हुआ। 26 और 27 नवंबर, 2015 को संविधान दिवस मनाने के लिए विशेष बैठक आयोजित हुई।'' उनके अनुसार, ''13 मई, 2012 को राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक हुई। 22 जुलाई, 2008 को वाम दलों द्वारा संप्रग-1 सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए लोकसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया।'

साथ ही कांग्रेस ने अदाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग बुधवार को फिर उठाई और कहा कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी के गठन की घोषणा के साथ संसद के नए भवन में कामकाज का आगाज होना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया है कि अदाणी समूह से संबंधित एक पूर्व कांट्रैक्टर ने उच्चतम न्यायालय से इस समूह से संबंधित मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। अमेरिकी कंपनी 'हिंडनबर्ग रिसर्च' द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ 'अनियमितताओं' और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर हमले और जेपीसी से जांच की मांग कर रही है। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और उसका कहना था कि उसकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया है।

रमेश ने बुधवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'कुछ दिन पहले अदाणी महाघोटाले की सही ढंग से जांच करने में सेबी की विफलता पर विस्तृत दस्तावेज के साथ उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। अब अदाणी से संबंधित एक पूर्व कांट्रैक्टर करोड़ों निवेशकों के हित में इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमति चाहता है। इस कांट्रैक्टर का कहना है कि उसके पास अंदरूनी जानकारी है।' उन्होंने कहा, 'यह सब जेपीसी से जांच की मांग को मजबूती देता है। यदि प्रधानमंत्री के पास वास्तव में छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की घोषणा के साथ नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत हो सकती है।'

खेल
प्रमुख समाचार

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज

कोलंबो। गुरुवार को एशिया कप के अपने अंतिम सुपर 4 मैच में श्रीलंका का सामना बाबर आजम की पाकिस्तान से होगा। उम्मीद है कि मौजूदा चैंपियन प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपने घरेलू मैदान का भरपूर फायदा उठाएगा। वर्चुअल सेमीफाइनल का विजेता रविवार को एशिया कप फाइनल में भारत से खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद तीन बजे शुरू होगा। यदि वर्चुअल सेमीफाइनल रद्द हो जाता है, तो जिस टीम का नेट रन रेट बेहतर होगा, वह एशिया कप फाइनल में भारत के साथ शामिल होगी। मौजूदा स्थिति के अनुसार, नेट रन रेट के मामले में श्रीलंका को पाकिस्तान पर बढ़त हासिल है। भारत दो मैचों में चार अंकों के साथ सुपर 4 चरण में अग्रणी स्थान पर है। मेन इन ब्लू के बाद श्रीलंका है, जो पाकिस्तान के साथ अंकों के स्तर पर है। चोटों से जूझ रहा पाकिस्तान और अपने कुछ खिलाड़ियों के उत्साहजनक प्रदर्शन से आत्मविश्वास हासिल करने वाला श्रीलंका एशिया कप एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए गुरुवार को यहां एक दूसरे का सामना करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के दो-दो अंक हैं और इस तरह से गुरुवार को होने वाला मैच एक तरह से नॉकआउट मैच बन गया है जिसमें जीत दर्ज करने वाली टीम 17 सितंबर को होने वाले फाइनल में जगह बनाएगी। भारत मंगलवार को सुपर चार के मैच में श्रीलंका को 41 रन से हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अभी चार अंक लेकर शीर्ष पर है। पाकिस्तान की टीम चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही है और पूरी संभावना है कि उसके प्रमुख तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और नसीम शाह श्रीलंका के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लगातार 9वें दिन चढ़कर सेंसेक्स 67,466 पर बंद

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले नकारात्मक रुझानों के बावजूद हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार 9वें दिन हरे निशान पर बंद हुए। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 246 अंकों की उछाल दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी 77 अंको की बढ़त के साथ नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले कारोबार की शुरुआत में स्थानीय शेयर बाजारों में आठ दिन के तेजी के सिलसिले पर ब्रेक लगा और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में लगभग 168 अंक टूट गया। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी से बाजार धारणा प्रभावित हुई। इसके अलावा घरेलू बाजार के ऊंचे मूल्यांकन की वजह से भी निवेशकों ने सतर्कता बरती। हालांकि अगस्त के लिए उम्मीद से बेहतर रिटेल महंगाई डेटा ने धारणा को बढ़ावा दिया।

31 तक यात्री वाहन बाजार का साइज दोगुना होने की उम्मीद

नईदिल्ली। देश का यात्री वाहन उद्योग सालाना 60 से 70 लाख इकाइयों के आंकड़े को छूने को तैयार है, ऐसे में परिचालन को स्थिर और पर्यावरण अनुकूल बनाने की जरूरत है। मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेयूची ने बुधवार को यह बात कही। ताकेयूची ने बुधवार को यहां वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एक्मा) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ''आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक यात्री वाहन बाजार का आकार सालाना 60 से 70 लाख इकाई तक पहुंच जाएगा।''उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि परिचालन का पैमाना मौजूदा स्तर का लगभग दोगुना होगा।

कॉफी डे ग्लोबल का इंडसइंड बैंक से समझौता

नईदिल्ली। कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड (सीडीजीएल) और उसके वित्तीय ऋणदाता इंडसइंड बैंक के बीच समझौता हो गया है। इस समझौता के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी के खिलाफ दिवाला आदेश को रद्द कर दिया है। यह कंपनी कॉफी चेन कैफे कॉफी डे का परिचालन करती है। सीडीजीएल और इंडसइंड बैंक के वकील ने बुधवार को एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ को समझौते के बारे में सूचित किया और दिवाला मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल और श्रीशा मेरला की दो सदस्यीय पीठ ने उनकी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया और सीडीजीएल को दिवालिया घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया। इससे पहले 11 अगस्त को एनसीएलएटी ने एक अंतरिम आदेश के जरिये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सीडीजीएल के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

गति को त्योहारी सीजन में 18-20% ग्रोथ की उम्मीद

नईदिल्ली। माल-ढुलाई कंपनी 'गति' ने त्योहारी सीजन के दौरान ई-कॉमर्स और फ्रिज, एसी जैसे बड़े इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसी वस्तुओं की ढुलाई की मांग में इस साल 18-20 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद जताई है। कंपनी ने कहा कि इस संभावित मांग की आपूर्ति करने के लिए उसने भंडारण और सेवा आपूर्ति क्षमता बढ़ाकर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गति ने बयान में कहा कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक मेगा सरफेस ट्रांसशिपमेंट सेंटर और वितरण गोदाम के अलावा उसने हरियाणा के फरुखनगर, मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के नागपुर और असम के गुवाहाटी में सरफेस ट्रांसशिपमेंट सेंटर (एसटीसी) भी हैं। गति एक्सप्रेस एंड सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड (जीईएसपीएल) ने कहा कि कंपनी त्योहारी सीजन के दौरान उन क्षेत्रों में लघु एवं मझोले उद्यमों को भौगोलिक रूप से विविध बाजार बनाने में मदद करेगी।

लाभप्रद होगा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर

डॉ राजन कुमार

दिल्ली में जी-20 के शिखर सम्मेलन के मौके पर कई बड़ी घोषणाएं हुईं। इनमें एक महत्वपूर्ण घोषणा थी- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर का विकास। यह भारत को मध्य पूर्व के देशों के रास्ते यूरोप से जोड़ने के लिए एक बहुउद्देशीय परिवहन गलियारा होगा जिसका उद्देश्य आधारभूत ढांचे का विकास करना होगा। इस परियोजना पर काम करने के लिए भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने समझौते किये हैं।

इस परियोजना को चीन की बहुचर्चित बीआरआई या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव परियोजना और उसके जरिये भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की चीन की कोशिश का मुकाबला करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। परिवहन नेटवर्कों के माध्यम से महाद्वीपों को जोड़ना 21वीं सदी की भू-रणनीतिक विशेषता बन गयी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान में बीआरआइ परियोजना की घोषणा की थी, जो मूल रूप से पूर्वी एशिया और यूरोप को जोड़ने का प्रयास था। चीन के इस कदम के बाद से ही अन्य देशों ने भी वैकल्पिक मार्गों और रणनीतियों की खोज शुरू कर दी है।

पहले वन बेल्ट वन रोड के नाम से जानी जाने वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शी जिनपिंग की विदेश नीति की पसंदीदा परियोजना है। योजना के दो पहलू थे- भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट और समुद्री सिल्क रोड। बीआरआइ में शामिल होने के लिए अब तक करीब 147 देशों ने एमओयू या सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये हैं। चीन अब तक इस परियोजना पर एक

ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। इसमें सबसे बड़ा निवेश चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर हुआ है, जिसका अनुमानित निवेश 62 अरब डॉलर है।

बहरहाल, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा भारत के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है। पाकिस्तान द्वारा पैदा की गयी बाधा के कारण भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा विकसित करने में असमर्थ रहा है। अमेरिकी समर्थन के बावजूद तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआइ) पाइपलाइन सफल नहीं हो पायी है।

भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आइएनएसटीसी) पर कड़ी मेहनत की है, जो ईरान और मध्य एशिया में बंदरगाहों के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ने का एक वैकल्पिक मार्ग है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास पर लगभग 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया, और यह चाहता था कि इसे आइएनएसटीसी में शामिल किया जाए। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस परियोजना को बाधित कर दिया है।

नया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन गया है। इसका एक बड़ा लाभ यह है कि इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त राशि है। आइएनएसटीसी की तरह, यह स्वेज नहर मार्ग की तुलना में पारगमन समय को 40 प्रतिशत और माल ढुलाई लागत को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है। भारत के पूर्वी तट से माल जहाज के माध्यम से अरब प्रायद्वीप तक पहुंचेगा, जहां से इसे सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से यूरोप तक पहुंचाया जायेगा। भारत के मध्य पूर्व और यूरोप के देशों के साथ उत्कृष्ट व्यापारिक संबंध हैं। यह तीनों क्षेत्रों के लिए लाभप्रद स्थिति हो सकती है। यह व्यापार को बढ़ायेगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। भू-राजनीति के संदर्भ में, यह छोटे देशों को आकर्षित कर सकता है जो बीआरआइ पर बहुत अधिक निर्भर हो गये हैं। हालांकि, चीन के बीआरआइ का मुकाबला करने की दिशा में यह एक छोटा कदम है। चीन ने पूरी दुनिया में अपना जाल फैला रखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा

कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

रायपुर। रायगढ़ जिले की धरती पर लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। इस मौके को बड़ा बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ के कोंड़ातराई में जनसभा लेंगे। इस दौरान वे चार रेल लाइन परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। एक लाख सिकलसेल मरीजों को कार्ड का वितरण भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा की पल-पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया एक्स पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही राज्यों के चौतरफा विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी कड़ी में कल कई बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिलेगा। इससे यहां रहने वाले लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के नए-नए द्वार खुलेंगे।

28 सितंबर को पीएम मोदी दूसरी बार आएंगे छत्तीसगढ़

चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। अगले 15 दिन के भीतर वह दो बार छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। रायगढ़ में दौरे के बाद दूसरा दौरा 28 सितंबर को फिर से है। भाजपा की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही है परिवर्तन यात्रा के समापन के दिन बिलासपुर में प्रधानमंत्री की सभा प्रस्तावित है।

50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लाक

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 210 करोड़ रुपये की लागत की 50 बिस्तरों वाले %%क्रिटिकल केयर ब्लाक%% का भी शिलान्यास करेंगे। इनमें दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिला शामिल है

छत्तीसगढ़ विस चुनाव 2023 में बीजेपी का लक्ष्य जीत

छत्तीसगढ़ में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 2023 में जीत सुनिश्चित करने के साथ-साथ भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 को लक्ष्य बनाकर चल रही है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्रों में से नौ सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी रायपुर में लगभग 7,600 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था।

इन्हें मिलेगा सिकलसेल परामर्श कार्ड

विशेष रूप से जनजातीय जनसंख्या के बीच सिकल सेल रोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से, सिकल सेल रोग की जांच की गई है। प्रधानमंत्री एक लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण करेंगे

यहां पर्यटन और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण 516 करोड़ में हुआ है। यह 50 किमी लंबी है। चांपा- जामगा रेलखंड के बीच 98 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण 796 करोड़ से किया गया है। नई रेल लाइनों से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पर्यटन-रोजगार दोनों के अवसर बढ़ेंगे।

यहां बढ़ेगी कनेक्टिविटी

छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण-1 को महत्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति-बहुआयामी-माडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें खरसिया से धरमजयगढ़ तक 124.8 किलोमीटर की रेल लाइन शामिल है, जिसमें गारे-पेलमा के लिए एक छोटी लाइन और छाल, बरौद, दुर्गापुर व अन्य कोयला खदानें को जोड़ने वाली 3 फीडर लाइनें शामिल हैं। लगभग 3,055 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह रेल लाइन विद्युतीकृत ब्राड गेज लेवल क्रासिंग और यात्री सुविधाओं के साथ फ्री पार्ट डबल लाइन जैसी व्यवस्था से सुसज्जित है। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों से कोयला परिवहन के लिए रेल सुविधा देगी।

ये प्रमुख रेल परियोजनाएं

रेल परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण-1, चंपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस) से जोड़ने वाली एमजीआर (मेरी-गो-राउंड) प्रणाली शामिल है।

भाजपा का एकदिवसीय धरना, कार्यकर्ता बोले -जनता त्रस्त भूपेश और महापौर मस्त

रायपुर। भाजपा रायपुर शहर जिला द्वारा पूर्व मंत्री राजेश मूणत एवं जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में आमापारा बाजार स्थित कारी तालाब के सामने एकदिवसीय धरना दिया रायपुर नगर निगम के रहवासियों के लिए डेंगू , खुले गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं गरीब पट्टे की बांट जोह रहा है संपत्ति कर माफ का वादा पूरा होने का इंतजार करते करते थक चुके हैं ऐसे में भी नगर निगम तो कुंभकर्णी निद्रा में लीन हो चुका है इन्ही सब मांगो को लेकर भाजपा रायपुर शहर जिला द्वारा आज धरना दिया गया, *भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत* ने कहा की गरीब मर रहा है मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है ना ही प्रदेश सरकार और ना ही महापौर । किसी को गरीब की सुध लेने का समय नहीं है रोजाना डेंगू से लोगो की जान जा रही जवाबदेही इसकी जवाब देही कौन तय करेगा सड़को और गलियों पर खुले गढ्ढे हैं जो अब जानलेवा होते जा रहे हैं रोजाना कोई ना कोई गढ्ढे के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहा है आज सैकड़ों की संख्या में नागरिक धरना देने आये हैं और अगर महापौर अभी भी नही जागे तो उग्र प्रदर्शन किया जायेगा। धरने को संबोधित करते हुए जिला *भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल* ने कहा की शहर की जनता में त्राहिमाम है और निगम प्रशासन सो रहा है हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक निगम प्रशासन और निष्क्रिय महापौर जाग नही जाते पट्टे का वादा पूरा करना होगा , संपत्ति कर माफ किया जाना चाहिए, जो की अतिरिक्त वसूला जा रहा है किस्मत के महापौर जी जनता उत्तर देना जानती है और अब तो समय भी आ रहा है परिणाम के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार रहे । धरने को संबोधित करते हुए नगरीय निकाय के प्रदेश संयोजक प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने कहा कि शहर का महापौर के कानों में जूं क्यों नही रेंग रहा है यह समझ से परे है। शहर में डेंगु से लगातार मौतें हो रही हैं। भूपेश बघेल अपनी राजनीति साधने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी में उनका वर्चस्व खत्म न हो जाय इसी जद्दोजहद में लगे है। अपने चहेतों को टिकट दिलवाने की जुगत में हैं।

दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे नड्डा 15 को आएंगे जशपुर

रायपुर। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी वापसी करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है. इसी कोशिश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सितंबर को जशपुर से विजय यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने आ रहे हैं.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार जेपी नड्डा 15 सितंबर को पुणे से विशेष विमान में बैठकर रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से जशपुर पुलिस लाइन हेलीपैड में 11ः40 बजे उतरेंगे. इसके बाद कार से पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह जाएंगे. 12.25 बजे से 12.45 बजे तक भगवान बालाजी मंदिर में पूजा पाठ में शामिल होंगे. 1.10 बजे रणजीता स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां 3ः10 बजे तक वे आमसभा विजय परिवर्तन कार्यक्रम में रहेंगे. इसके बाद वापस हेलिकॉप्टर से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन से पुणे रवाना होंगे.विजय परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे. दूसरे चरण की यात्रा 14 जिलों की 39 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें कई आमसभाएं होंगी. इस यात्रा में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे।

पीएम के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगाः सिंहदेव

अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को रायगढ़ के प्रवास पर आ रहे हैं, जहां वे भाजपा की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की आमसभा को लेकर भाजपाइयों में उत्साह है। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री के प्रवास से मतदाताओं में फर्क नहीं पड़ेगा।

अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्रीय नेताओं के आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से टॉप लीडर्स आते हैं तो एक उत्साह बनता है। कांग्रेस के भी टॉप लीडर्स के आने का सिलसिला पिछले दो माह से चल रहा है। प्रियंका गांधी दो बार आकर जा चुकी हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आकर जा चुके हैं। फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है। ये सतत नेताओं का कार्यक्रम होते रहते हैं, खासकर चुनाव के पहले। वहीं क्रम भाजपा में चल रहा है। नेता आएंगे और चले जाएंगे। मतदाता के लिए मुख्य मुद्दा होता है- स्थानीय क्या है? स्थानीय विकल्प देखते हैं कि कांग्रेस है, भाजपा है, अन्य दल हैं। हमारा भविष्य ज्यादा सुरक्षित किसके हाथ में है। सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है। बाहर के नेताओं का आना कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ाता है, लेकिन मतदाता हमेशा सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करता है।

नरेंद्र मोदी लड़ेंगे चुनाव तो फर्क पड़ेगा

डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में काम नहीं करना है। पांच साल हो गए वे एक बार भी नहीं आए होंगे। आए होंगे तो एकात बार आए और चले गए। मतदाता जानता है कि यह प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी यहां आकर चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ेंगे तो फर्क पड़ सकता है। वो बोले कि अब मैं छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का काम करूंगा, तो लोग सोचेंगे कि मोदी का भाजपा से मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वोट दें कि न दें। वो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली का काम प्रदेश को विशेष कोई प्रभाव नहीं डालता है।

बिना कारण नहीं कटेगी टिकट-कांग्रेस विधायकों का टिकट कटने के सवाल पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बिना कारण किसी का टिकट नहीं कटेगा, चाहे वह मंत्री हो, संसदीय सचिव हो, विधायक हो। पांच साल पहले जनता ने उन्हें चुना है। कोई कारण होगा तभी टिकट कटेगी। इसलिए ही समीक्षा हो रही है, अन्यथा पिछले 71 सभी को टिकट दे दिया जाता।

नरेंद्र मोदी के राज में अब गरीब की थाली से दाल भी गायब

रायपुर। बेलगाम महंगाई पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। केंद्र सरकार की गलत नीति का परिणाम है बेलगाम महंगाई। जिसका खामियाजा गरीब एवं मध्यम वर्गीय को भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार के राज में गरीबों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मोदी सरकार के राज में राहर दाल प्रति किलो 180 रू. हो गया है। मध्य एवं गरीब वर्ग के बजट से राहर दाल भी बाहर हो गया है। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा यह गलत कहा था जबकि वास्तविकता यह है कि मोदी जी 56 भोग खा रहा है और मध्य गरीब परिवारों के मुंह से दाल भात का निवाला भी छीन रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि महंगाई के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री स्मृति ईरानी की हिम्मत नहीं हो रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.